



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

मई दिल्ली, बुधवार, विसम्बर 12, 1979/अग्रहायण 21, 1901

No. 524] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वर्षी जारी हैं जिससे कि उह अलग संकलन के लिए रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई संचालन
(सिंचाई विभाग)

अधिसूचना

मई दिल्ली, 12 विसम्बर, 1979

का.आ. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राजिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 4055, तारीख 6 अक्टूबर, 1969 द्वारा, अन्तर्राजिक नदी नर्मदा और उसकी नदी घाटी की दावत जल विवाद का अधिनियम करने के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया था;

और उक्त अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में अन्वेषण किया तथा अपनी एक रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार की अधिकृत तीर्थी जिसमें, वे तथ्य कर्तित हैं जो उसके समक्ष आए थे और उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका दिनिक्षय भी दिया गया है;

और उक्त विनियोग पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार तथा गजराज, मध्य प्रदेश, झाहाराष्ट्र और राजस्थान, की सरकारों ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, उक्त अधिकरण को कर्तिपय विषय निर्दिष्ट किए थे और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों पर अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा के अधीन एक और रिपोर्ट अप्रीवित की है जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण और सार्वदर्शन दिए गए हैं जो उसने ठीक समझे हैं।

यह, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा उसकी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और सार्वदर्शनों के संबंध में यथा उपान्तरित उक्त अधिकरण के विनियोग को प्रकाशित करती है।

अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और सार्वदर्शनों द्वारा उपान्तरित फैल में नर्मदा जल विवाद अधिकरण का विनियोग

'अधिकारण का अन्तिम अधिकारण और विनियोग'

खण्ड 1: नर्मदा ग्रावर्टन की तारीख

गह यादेश उन तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसको इस अधिकरण के विनियोग अन्तर्राजिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन, रामपत्र में प्रकाशित होते हैं।

खण्ड 2: सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा जल की उपयोग सांवाद का अद्यारण

अधिकारण यह अवधारित करता है कि 75 प्रतिशत निर्भरता के अधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा के जल की उपयोग सांवाद 28 मिलियन एकड़ फुट ($34,537.44\text{एन.फ्यू.एम.}$) पर निर्धारित की जानी चाहिए।

खण्ड 3: नर्मदा जल की उपयोग सांवाद का प्रवर्तन

(1) अधिकरण यह यादेश करता है कि नर्मदा जल को उपयोग सांवाद में से, (क) मध्य प्रदेश 18.25 मि०ए०फ्यू० ($22,511.01\text{ मि०स्य०ग्य०}$) अंग का हकदार है, (ख) गुजरात 9 मि०ए०फ्यू० ($11,101.32$

मिंक्यू०मी०) धंश का हकदार है, (ग) राजस्थान ०.५ मि०ए०क्य० (८१६.७४ मि०क्य०मी०) धंश का हकदार है और (ब) महाराष्ट्र ०.२५ मि०ए०क्य० (३०८.३७ मि०क्य०मी०) के धंश का हकदार है।

(2) यह और स्पष्ट किया जाता है कि प्रभाजन का गम्भीर वास्तविक निकासियों से है, न कि उपयोग किए गए उपयोग से;

(3) प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने जल धंश के जल उपयोग के स्वरूप में और अपने राज्य क्षेत्र में नर्मदा तथा के भीतर या बाहर कायदा प्राप्त करने वाले छोड़ों में, ऐसे परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे वह आवश्यक समझे।

चरण 4: अतिरिक्त जल और करस्थल के संबंध में आवेदा

(1) किसी जल वर्ष में, प्रथम् १ जूनाई से अगले कलैण्डर वर्ष की ३० जून तक, उपयोज्य प्रवाह के २८ मि०ए०क्य० (३४,५३७.४४ मि०क्य०मी०) के प्राधिक्य में नर्मदा का उपयोज्य प्रवाह, आवंटन के निम्नलिखित अनुपात में प्रभाजित किया गया है, प्रथम्:—

मध्य प्रदेश के लिए ७३, गुजरात के लिए ३६, महाराष्ट्र के लिए १ और राजस्थान के लिए २;

(2) यदि १ जूनाई से अगले कलैण्डर वर्ष की ३० जून तक के किसी जल वर्ष में आवंटन के लिए उपयोज्य जल की उपलब्धता २८ मि०ए०क्य० (३४,५३७.४४ मि०क्य०मी०), से भी कम हो जाती है तो कभी विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश के लिए ७३, गुजरात के लिए ३६, महाराष्ट्र के लिए १ और राजस्थान के लिए २ के अनुपात में बांटी जानी चाहिए;

(3) किसी जल वर्ष में उपलब्ध उपयोज्य जल में, १ जूनाई को उपलब्ध भण्डारित जल के आधार पर उस तारीख को यथा निर्धारित पूर्वतन जल वर्ष से अप्रीली जल समिक्षित होगा;

(4) किसी तारीख को उपलब्ध उपयोज्य जल में सौटाव प्रवाह समिक्षित होगा किन्तु विभिन्न जलाधारों में से बांटीकरण के कारण हुई कमी उसमें से निकाल दी जाएगी।

(5) यह उल्लेखनीय है कि कई बांधों में भरण प्रविधि में, उस प्रविधि के द्वारा भण्डारण को पूरा करने और निकासी के पश्चात् कुछ अधिकरण जल होगा। यह समुद्र में बह जाएगा। उसका केवल कुछ भाग सरकार सरोवर नदी तक विजलीधर में विजली उत्पादन के लिए उपयोज्य होगा, और योग बेकार जाएगा। यह बांटीय है कि बह जल जो अन्तिम नदी तक विजलीधर में शक्ति का उत्पादन किए जिन बेकार जाएगा, पक्षकार राज्यों को, जिस विस्तार तक वे चाहें, उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसलिए गुजरात को, यह निर्देश दिया जाता है कि जब कभी जल शक्ति उत्पादन किए बिना समुद्र में बेकार जाना आवश्यक हो, या वह ऊपरी नेतृत्व स्टेशनों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्रत्यापा करता है कि जल इस प्रकार बेकार जाएगा, तो वह नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) और सभी सम्बद्ध राज्यों के अधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित करेगा और वह उन्हें तब भी सूचित करेगा, जब ऐसा प्रवाह रुक जाता है। ऐसे प्रवाह की प्रवधि के द्वारा ऐसे पक्षकार राज्य, जिनके अलाप्य छलक रहे हैं और छलकता जल अन्यत भण्डारित नहीं किया जा सकता, उसके जलाधारों से बहाव वा ऐसा उपयोग कर सकेंगे, जैसा वे चाहें, और पक्षकार राज्यों द्वारा ऐसे उपयोग की गणना उद्देश्य आवंटित प्रवाह में नहीं की जाएगी, किन्तु ऐसे जल का उपयोग किसी उपभारित अधिकार की स्थापना नहीं करेगा।

चरण 5: प्रभाजन आवेदा के प्रबलन की अवधि

चरण 3 और 4 में साम्यान्तरीय आवंटन के संबंध में हमारे पांच, राजपत्र में अधिकरण के विनियोग के प्रकाशन की तारीख से ४५ वर्ष की प्रवधि के पश्चात् किसी भी समय गुनविलोकन के अधीन रहे हुए, लिए गए हैं;

चरण 6: नवगांधी भाहर का पूर्ण प्रवाह स्तर

अधिकरण यह अधिकारित करता है कि भगवान् सरोवर से जल प्राप्त करने वाली नवगांधी नहर का पूर्ण प्रवाह स्तर, उसके शीर्ष रेग्युलेटर पर ९१.४४ मी० (+ ३००') नियन्त्रित किया जाना चाहिए और उसकी तल ढानान शीर्ष से २९० किमी० (१८० मील) तक, प्रथम् जहां से सौराष्ट्र ग्रामा जल प्राप्त करती है, १२,००० में १ के हिसाब से होता चाहिए। उस विन्यु से राजस्थान सीमा तक तल ढानान १०,००० में १ के हिसाब से होना चाहिए। ये तल ढानान पारस्परिक करार से गुजरात और राजस्थान द्वारा परिवर्तित की जा सकती। गुजरात और राजस्थान, उस जल के कारण जिसकी उपलब्धता उनके धंश के भीतर मंबाजित होगी, प्रत्येक द्वारा प्रयोगित नहर धारिता का विनियोग करने के लिए स्वतंत्र होगे।

चरण 7: सरकार सरोवर बांध का पूर्ण जलाशय स्तर और अधिकतम जल स्तर

अधिकरण यह अधिकारित करता है कि सरकार सरोवर बांध की ऊंचाई पूरी जलाशय स्तर पर + १३८.६८ मी० (+ ५५५') और अधिकतम जल स्तर पर + १४०.२१ मी० (+ ५६०') नियन्त्रित की जानी चाहिए। गुजरात तदनुसार आधा का मनिमणि हाथ में लेगा और उसे पूरा करेगा।

चरण 8: लागत और कायदे में हिस्सा बांध :

(1)(1) अधिकरण यह अधिकारित करता है कि किसी भी दिन नहर के शीर्ष और नदी तल विजलीधरों के नवगांधी पर उत्पादित शुद्ध शक्ति में से मध्य प्रदेश का धंश ५७ प्रतिशत होगा; महाराष्ट्र का धंश २७ प्रतिशत होगा और गुजरात का धंश १६ प्रतिशत होगा।

(2) पक्षकार राज्य, अनुमोदित समिक्षण कार्यक्रम के अनुभार अपेक्षित विधियों में अपने धंश वार्षिक किलों में उपलब्ध करेंगे और राजपत्र में अधिकरण के अन्तिम आदेश और विनियोग के प्रकाशन की तारीख से बस वर्ष के भीतर सरकार सरोवर बांध को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

(2) अधिकरण निम्नलिखित और आवेदा करता है:—

(1) नवगांधी पर सभी तल और नहर विजलीधरों में जलावृत्त शक्ति सामान्य स्विच्याई में जमा की जाएगी।

(2) स्टेशन सहायकों के लिए अनुग्रात करने के पश्चात् स्विच्याई में बस बार पर उपलब्ध शक्ति में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः ५७ प्रतिशत और २७ प्रतिशत प्राप्त करने के हक्कदार होंगे।

(3) उपर्युक्त हक्कदारी शिखर भार के लिए मासीन धारिता की उपलब्धता और किसी एक दिन में उत्पादित कूप ऊर्जा, बोनों का, लागू होती है।

(4) किसी भी दिन के लिए विशुद्ध और ऊर्जा की हक्कदारी, सम्बद्ध राज्यों द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त को या पारस्परिक करार के प्रधीन किसी अन्य भागीदार राज्य को भेजनी जा सकती है। किन्तु इसे प्रमाणित पक्षकारों में किए गए पूर्धक करार या कार्यालयी, प्रबन्ध के अधीन के विभाग, अपनीत नहीं किया जा सकता है।

(5) गुजरात, पक्षकारों के बीच यथा तथा का गई सरेक्षा के साथ-साथ और यदि कोई करार नहीं किया गया है तो, ऐसी सरेक्षा के साथ-साथ, जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारी विनियोग करे, गुजरात राज्य सीमा तक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विद्युत की आवंटित मात्रा प्रवाह करने के लिए आवश्यक पारेक्षण लाइनों का समिक्षण और उनका अनुरक्षण करेगा। गुजरात राज्य सीमा के परे पारेक्षण लाइनों का समिक्षण और अनुरक्षण, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपने अपने राज्यों में करेंगे।

- (6) गुजरात राज्य में विजलीधरों और ग्रनुलम संकर्मी, जिसके अन्तर्गत मरींगे और सभी प्रतिष्ठापन तथा पारेशन लाइनें भी हैं, का संश्लिष्टि, अनुरक्षण और प्रचालन गुजरात राज्य वा उस राज्य द्वारा निम्नविष्ट कोई प्राधिकारी करेगा।
- (7) विजली धरों का नियंत्रण प्राधिकारी, जहो तक जल के उपयोग का संबंध है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देशों का अनुरक्षण करेगा।
- (8) विजलीधरों के प्रचालन की स्कीम, जिसके अन्तर्गत दिन के विभिन्न भागों के दौरान, विभिन्न पक्षकार राज्यों के निए अपेक्षित शक्ति और जुटा या जाने वाला भार भी हैं, प्रत्येक मास के प्रारम्भ से कम से कम एक सत्राह पूर्व राज्यों के बीच तथा की जाएगी और राज्यों के बीच करार के अधीन या आपातकानीन स्थितियों में के सिवाए, मास के दौरान परिवर्तित नहीं की जाएगी। जब कभी सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र, प्रावेशिक या राष्ट्रीय शक्ति प्रिष्ठ के साथ संयोजित हो जाता है, तो सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र का प्रचालन ऐसी परिवर्तित प्रणाली की शर्तों से शासित होगा। किन्तु उस स्थिति में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को, इन प्रावेशों के अनुसार सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र से शक्ति और उर्जा का अपना हक प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए यावद्यक है।
- (9) नवगाँव प्रक्षेत्र के शक्ति भाग की पूँजी लागत में निम्नलिखित होगे:—
- (क) यूनिट-III विद्युत संकर्मों और लिव्याई तक, जिसके अन्तर्गत वह भी है, उससे संबंधित नियंत्रण संकर्मों को पूर्ण लागत।
- (ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को शक्ति प्रदाय के लिए संश्लिष्टि गुजरात राज्य में पारेशन लाइनों की पूर्ण लागत।
- (ग) सामान्य सुधाराधारों, जैसे बोर्ड और ग्रनुलम संकर्म, प्रथात् सरदार सलोवर परियोजना की यूनिट 1 की यूनिट लागत का, जिसमें से जमा रकमों को, यदि कोई हो, घटा दिया जायेगा, में 56.1 प्रतिशत।
- (घ) नर्मदा सागर बांध से व्युत्पन्न अनुप्रवाह कामदों के लिये मध्य प्रदेश को दिए गए जमावातों का 56.1 प्रतिशत।
- (10) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर (9) के अनुसार निकाली गई सरदार सरोवर शीर्ष संकर्म के शक्ति धरण की पूँजी लागत का कमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत गुजरात को संदर्भ करें यह राशि, जब तक पूँजी संकर्म पूरे नहीं हो जाने, वाचिक किस्तों में संदर्भ की जायेगी। प्रत्येक किस्त प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में संकर्म के बफ्ट-अंकों के भास्तार पर निकाली जायेगी और वित्त वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक अंकों के अनुसार मुजरा और समायोजित की जायेगी।
- (11) ऊपर (10) के अनुसार संदर्भों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक वर्ष सरदार सरोवर प्रक्षेत्र के प्रचालन और अनुरक्षण लागत का कमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत भी गुजरात को होंगे। ये संदाय भी प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में बजट अंकों पर प्राप्तिकरण होंगे और वर्ष के द्वान में वास्तविक लागत के अनुसार समायोजित किए जायेंगे।
- (12) इसमें ऊपर अन्तर्भित गिरेंगों के होते हुए भी पक्षकार राज्य पारस्परिक करार द्वारा, शक्ति के विभाजन और उसके

लिये संदाय की बाबत किसी भी प्रदेश को परिवर्तित, संशोधित या उपायात्मित कर सकें।

बण्ड 9: सरदार सरोवर परियोजना की अपेक्षा के लिए मध्य प्रदेश द्वारा नियमित रूप में छोड़ जाने वाला जल

प्रधिकरण, नियमित रूप में छोड़ जाने वाले जल की मात्रा और रीति के संबंध में निम्नलिखित आवेदा करता है:—

पक्षकार राज्यों ने यह तय कर दिया है और प्रधिकरण ने सारीज 8 अक्टूबर, 1974 के अपने आवेदा में यह विनियमित कर दिया है कि सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा में 75 प्रतिशत निर्भर योग्य जल की उपयोग मात्रा, 28 एम ए एफ (34, 537. 44 मि० क्य० मी०) पर निर्धारित की जानी चाहिये। किन्तु 75 प्रतिशत निर्भर योग्यता का वास्तविक अनुप्रवाह के बीच 33, 316. 29 मि० क्य० मी० (27. 01 एम ए एफ) है और इसे, वालीकरण से होने वाली कमियों और पुनः उत्पादन की बाबत छूट को छोड़कर, विभिन्न जलाशयों में भित्ति बढ़ाने द्वारा 28 एम ए एफ (34, 537. 44 मि० क्य० मी०) की उपयोग मात्रा तक लाया जाता है। सरदार सरोवर पर 28 एम ए एफ (34, 537. 44 मि० क्य० मी०) में से 11, 101. 32 मि० क्य० मी० (8 एम ए एफ) की व्यावस्था गुजरात के लिये और 0. 5 एम ए एफ (616. 74 मि० क्य० मी०) की व्यवस्था राजस्थान के लिये भी जानी है। सरदार सरोवर पर अपेक्षाओं को मध्य प्रदेश प्रदायों से और नर्मदा सागर के नीचे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अपेक्षाओं को प्रधिशेष तथा मध्यवर्ती जलाशयों के अनुप्रवाह से पूरा किया जाना है, महेश्वर से छोड़ा गया जल 10, 015. 86 मि० क्य० मी० (8. 12 एम ए एफ) भारी है मासिक रूप में छोड़े गए जल को एकरूपता देने के लिये मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल की मात्रा, प्रति मास 834. 65 मि० क्य० मी० (0. 677 एम ए एफ) होगी। किन्तु नदी प्रणाली में वास्तविक अनुप्रवाह वर्ष प्रति वर्ष अन्तर्भित होगा, यह मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल की मात्रा भी अप्राप्ति होगी।

जुलाई से अक्टूबर तक की घरण घवधि के दौरान अनुप्रवाह की अविद्यालयी भौमिक के प्रारम्भ में नहीं की जा सकती। केवल अक्टूबर में ही यह पूर्णतः जात होगा कि विधिष्ट वर्ष सामान्य वर्ष है या किसी सीमांतक घवधियों या कमी वाला वर्ष है। यह मासान्धीतः भरण घवधि के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा छोड़ा जाने वाला जल लगभग 28 एम ए एफ (34, 537. 44 मि० क्य० मी०) उपयोग मात्रा देने वाले वर्ष के आवार पर होगा। जुलाई मास और घरण का प्रारम्भिक भाग खारीफ बुधाई के लिये महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि इस घवधि के दौरान विनियमित प्रबन्ध द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी पक्षकारों को जल का सम्पूर्ण उपलब्ध हो जाये।

पूर्ववर्ती यों पैरों में उत्स्थित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रावेश करते हुए कि विनियमित और जल गणना के लिए विस्तृत नियम, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नीचे दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार बनायेगा। किन्तु वे मार्गनिर्देश संबद्ध राज्यों के बीच करार द्वारा परिवर्तित, संशोधित या उपायात्मित किये जा सकेंगे।

- (1) किसी जल वर्ष (1 जुलाई से अगस्त वर्ष 30 जून तक) में 75 प्रतिशत निर्भर योग्य 28 एम ए एफ (34, 537. 44 मि० क्य० मी०) उपयोग प्रदाय का विभाजन पक्षकार निम्नलिखित रूप में करेंगे।
- मध्य प्रदेश — 18. 25 एम ए एफ (22, 511. 01 मि० क्य० मी०)
- गुजरात — 9. 00 एम ए एफ (11, 101. 32 मि० क्य० मी०)
- राजस्थान — 0. 50 एम ए एफ (616. 74 मि० क्य० मी०)
- महाराष्ट्र — 0. 25 एम ए एफ (308. 37 मि० क्य० मी०)

(2) किसी जलवर्ष में उपयोग प्रदायों का अधिकार या कभी पक्षकार राज्य उसी अनुपात में साध्य सीमा तक बढ़ायेगे, जिसमें उपर (1) में उनके आवंटित अंश हैं अधिशेष जल का उपयोग प्रथमतः धारिता तक जलाशयों को भरने के लिये किया जाएगा और तत्पश्चात उसका उपयोग सिवाई और अस्थ प्रयोजनों के लिये केवल तभी किया जाएगा, जब ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया हो।

(3) 30 जून को विभिन्न जलाशयों के चालू भण्डारों में उपलब्ध जल की गणना अगले जल वर्ष में बढ़ायेगी जाने वाले अन्तःप्रवाह के रूप में की जाएगी।

(4) किसी जल वर्ष में राजस्थान और गुजरात का जल प्रांत सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक जल ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो अधिकारी निर्दिष्ट या अनुमोदित करे और नियमित रूप में छोड़ जाने वाले जल के निवेशों को बृहिं में रखते हुए, युक्तपूर्ण सामान्य दर पर मध्य प्रदेश उतारें।

(5) प्राधिकरण, मध्य प्रदेश द्वारा छोड़ जाने वाले जल का ऐसा निवेशन करके यह मुनिश्चित करेगा कि अगले दस दिन की अवैश्यों को पूरा करने के लिये सरदार सरोवर में पर्याप्त उपयोग जल हर समय बना रहे किंतु गर्ते यह होगी कि मध्य प्रदेश की अनुपातिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद मध्य प्रदेश में भण्डारों में जल उपलब्ध बना रहे। इस प्रयोजनार्थ गुजरात और राजस्थान 10 दिन का अवधि की अपनी अपनी अपेक्षाएँ पर्याप्त समय पूर्व सूचित करें।

(6) प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा जल वर्ष में उपयोग, प्रत्येक मुख्य और मध्यम परियोजना के नगर मुख्य पर वास्तविक वैनिक निस्तारण के आधार पर अकित किया जायगा। गौण संकर्मों के लिए यह, अधिकारी फसलों के लिये सिंचित क्षेत्रों के, प्रत्येक फसल के लिये नदी मुख भूमि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर, आधार पर अंकित किया जायगा। पर्याप्त स्कीमों के लिये नदी, उसकी उपनिवेशों या जलाशयों से रिचाई घेरेलू और आपौर्योगिक उपयोग के लिये, लिए गए जल की गणना, पर्याप्त की नियन्त्रण द्वारा और उनके अन्तर्गत के घंटों की संडूच के आधार पर की जायेगी। प्रति पड़िताल के लिये प्रत्येक पर्याप्त स्कीम द्वारा भौमिक कम और फसल—कम से सिंचित क्षेत्र भी अभिविलित किया जायगा और यदि उपयुक्त दो पद्धतियों द्वारा प्राप्त जल की मात्रा में अन्तर आता है, तो, प्राप्त जल के संबंध में प्राधिकरण का विनिश्चित अंतिम होगा।

(7) गुजरात और राजस्थान के लिये नवगांव नहर के लिये सरदार सरोवर से निकाले गये जल की मात्रा नवगांव नहर परीक्षा पर की जायेगी। राजस्थान के लिये छोड़े गये जलकि माप गुजरात राजस्थान सीमा पर की जायेगी। राजस्थान को प्रदाय करने में नहर में हुई जल हानि का अवधारण नहर का सम्प्रभाव किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा किया जायगा और राजस्थान के अंश में उसकी मंगणना की जायेगी।

सरदार सरोवर के विभिन्नी पर टब्बिहों की मार्फत नदी में छोड़े गये जल का माप उसके द्वारा उत्पादित खालि के आधार पर और जो जल अधिक्षित मार्ग द्वारा रिस गया है उसकी माप अधिक्षित मार्ग पर की जायेगी।

गुजरात अपने अधिकार उपयोग के लिये विनिर्विद्ध मार्ग करके सरदार सरोवर से जल छोड़ सकेगा और ऐसे छोड़े गये जल की गणना उनके अंश के रूप में की जायेगी। अधिकार उपयोग के लिये ऐसा जल टब्बिहों की मार्फत छोड़ा जायेगा और इस प्रकार उत्पायित अपित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच विवित मनुपात में बांटी जायेगी। गुजरात की विशेष मार्ग को छोड़कर सरदार सरोवर से नदियों को छोड़ा गया जल, गुजरात के अंश रूप में नहीं गिना जायेगा।

मध्य प्रदेश और यथास्थिति, महाराष्ट्र में प्रयोग के लिये सरदार सरोवर से निया गया जल, उस राज्य के जल के हिस्से में गिना जायेगा।

(3) बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिये जल लेखा 10 वैनिक अवधि के रूप में रखा जायेगा। किसी मास की अन्तिम 10 वैनिक अवधि

उस मास के दिनों की संख्या के अनुमार 11 दिन, 10 दिन या उसमें कम की हो सकेगी। छोटी स्कीमों के लिये जल सेखा फाली भूमियों के अनुमार अर्थात् आरोफ (जुलाई में अक्टूबर तक) रखी (नवम्बर से भावें तक) तथा ग्रीष्म (अप्रैल से जून तक) रखा जायेगा। पर्याप्त स्कीमों आरो घरेलू तथा अपौर्योगिक उपयोग के लिये यह लेखा मासिक रूप में रखा जायेगा।

(9) छोटी और पर्याप्त स्कीमों द्वारा किसी वस वैनिक अवधि में जल के उपयोग को अनन्तिम रूप से उसी रूप में गिना जायेगा जैसा कि गत वर्ष में फसल अवधि के दौरान और अनुपयोग के आधार पर तत्समान अवधि के लिये या। किंतु अन्तिम जल लेखा उपर (6) के अनुमार अवधारित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक राज्य ऐसे आंकड़े और जानकारी जिसकी प्राधिकरण अपेक्षा कुरे और मार्ग, प्राधिकरण को देगा और उसकी इच्छा रखने वाले किसी पक्षकार राज्य को उपलब्ध करायेगा।

(11) प्राधिकरण मास में कम से कम एक बार, या यदि जल के छोड़े जाने में किसी परिवर्तन का निवेश देना आवश्यक समझा जाता है तो कितनी ही बार मध्य प्रदेश द्वारा इस दिन में छोड़े गये जल के पुनर्विलोकन की व्यवस्था करेगा वह ऐसा करने के लिये किसी व्यक्ति को अभिवृत्त कर सकेगा।

(12) प्राधिकरण किसी राज्य या राज्यों द्वारा पूर्ववर्ती जल वर्ष के दौरान उपयोग किए गए उस जल का यदि कोई है, जो अधिवृत्त उपयोग से अधिक है, पश्चात्वर्ती जल वर्ष में उन संबंधित राज्यों के बंधन या अर्थों में से जिन्होंने अधिक उपयोग किया है, कठौती करके अंतिम समायोजन करने के लिये निवेश देगा और उन राज्यों की प्रति करेगा जिन्हें कम प्रदाय प्राप्त हुआ है। राजस्थान को किसी भी विन उसकी मार्ग से 10 अंतिमत के उपर प्रदाय किए गए जल को गुजरात द्वारा उपयोग में लाए गए जल के रूप में गिना जायेगा।

(14) प्राधिकरण अगले जल वर्ष के अंत तक पक्षकार राज्यों की सरकारों को जल वर्ष के लिये वार्षिक जल लेखा ठीक आगले जल वर्ष के अगले मास के अंत तक ऐसे देगा। प्रत्येक राज्य लेखा पर अभ्यास अभिवृत्त अवधि कर सकता है और या उसमें उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर, अगुदियों यदि कोई है, बसा सकता है। आवश्यक उपलब्धता करने के पश्चात प्राधिकरण 21 अक्टूबर तक जल वर्ष का वार्षिक जल लेखा प्रत्येक पक्षकार राज्य को भेजेगा। प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष वार्षिक जल लेखा प्रकाशित कराएगा।

खण्ड 10--जल के ऐसे नियमित छोड़े जाने के लिये गुजरात मध्य प्रदेश को भुतान करेगा।

(1) मध्य प्रदेश, नमंदा सामर वान्ध एक प्रार २६२.१३ मी०एम (८६० फीट) के अधिभाग का कार्य आरम्भ करेगा और सरदार सरोवर वाय अधिकरण के संभिरणिके साथ साध या उसके पूर्व पूरा कर देगा।

(2) प्राधिकरण यह भी आवेद देता है कि गुजरात प्रति वर्ष नमंदा सामर आंध का नियमित कार्य आरम्भ होने के वर्ष से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में नमंदा भाग आंध मध्ये प्रतिवर्ष वर्ष का 17. 63 प्रतिशत मध्य प्रदेश खाते में जमा करेगा। इन आरम्भ में जमट भावेन के आधार पर जमा आते किया जायेगा जिसका समायोजन वास्तविक वर्ष के प्रभुत्वर वर्ष के अंत में किया जायेगा जिसका सम्प्रभाविति के पश्चात अनुरक्षण पर होने वाले अंदर को सम्प्रभाविति खाते के रूप में रही माना जायेगा।

खण्ड 11: जलप्रदायवस्था, भूमि अर्जन और विस्थायित अधिकारियों के पुनर्यास संबंधी नियम।

उपखण्ड 1: रिसायाएँ:—

(1) भूमि 'भूमि' शब्द का अर्थ, भूमि प्रति वर्ष नियम, 1894 में (जिसे इसमें प्राप्त 'भूमिनियम' कहा गया है) यथापरिभावित होगा अर्थात् भूमि शब्द से अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले कार्य और भूमि जीजे या भूबद्ध किसी भीजे के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई कोई जीजे हैं।"

(2) निर्वासित व्यक्ति—निर्वासित व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति प्रभिन्न है, जो अधिनियम की बाग 4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन भी तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व से उम्र क्षेत्रमें, जिसे स्थायी या अस्थायी रूप से जलमन किया जाना है, साधारण रूप से निवास कर रहा है, या खेती कर रहा है या कोई व्यापार, उपजीविका या आजीविका कर रहा है या लाभ के लिये कार्य कर रहा है।

(3) "कुटुम्ब" (1) कुटुम्ब के अन्तर्गत पति, पत्नी और अवयवक वज्रे और ऐसे अन्य व्यक्ति हैं जो कुटुम्ब के मुक्तिया पर अधिनियम द्वाहरणार्थ, विषया भाला।

(2) प्रस्तेक व्यस्त पुत्र को एक पृथक कुटुम्ब के रूप में भाला जायेगा उप खण्ड II—अनिवार्य रूप से अधिनियम की जाने वाली भूमि।

II(1) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार भरोवर परियोगना के लिये सरदार सरोवर के एक और एल + 138.38 मीटर (455फूट) नीचे स्थित प्राविष्ट स्वामित्व की सभी भूमि का और उसमें केंद्रे सभी हितों का जो संबंधित राज्यों के नहीं हैं, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपर्योगों के अधीन अर्जन करेंगे। यदि उपर्योग के प्राधार पर किसी व्यक्ति की संस्करण धृति की 75 प्रतिशत या अधिक भूमि को अनिवार्य रूप से अधिनियम किया जाना है तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण संस्करण धृति के अनिवार्य अर्जन के लिये शिवश कर सकेगा।

II(2) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपर्योगों के अंतर्गत उन सभी भवतों सहित उनका असुलग्न भूमि का भी जो एक भार एल + 138.68 भौं (455फूट) और एक इन्हूं एल + 141.21 मीटर (460भौं) के बीच स्थित है और जो एल 141.21 भौं (460फूट) के परिणाम स्वरूप पश्चात से प्रभावित है, अर्जित करेंगे।

II(3) सरदार सरोवर में उच्चतम स्तर पर पश्चात नह, केवल जन अधिनियम, मध्य प्रदेश और गुजरात से परामर्श करके निर्धारित करेगा।

उपखण्ड III—भूमि अर्जन और युक्तियां आदि के लिए प्रतिकर देने की वालत गुजरात का दायित्व।

III(1) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूर्वोक्त रूप में अर्जित किए जाने के लिए अधिकृत भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए या उसको धार्यत उनके द्वारा किए गए सभी खबरों का जिसके अन्तर्गत प्रतिकर, प्रभार और व्यय भी हैं, भुगतान करेगा।

III(2) गुजरात, सम्बद्ध सरकारी भूमि और संरचनाओं के लिए उन सिद्धान्तों पर, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अधोलिखित मिशनानों के अनुरूप हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत संघ को प्रतिकर देगा। यदि यथा पूर्वोक्त संदेश प्रतिकर के संबंध में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भारत संघ के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में से कोई राज्य या भारत संघ विवादप्रस्त मामले को माध्यस्थ्य के लिए निर्देशित कर सकेगा। एक प्रधानकार के रूप में गुजरात और दूसरे प्रधानकार के रूप में यथाविधिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य या भारत संघ, अपना एक एक मध्यस्थ नाम-निर्दिष्ट करेगा। मध्यस्थों के बीच मतभेद होने की दशा में, ऐसा विवाद या मतभेद किसी ऐसे नियन्यक को निर्विट किया जाएगा जिसकी नियुक्ति इस नियमित भारत के मुख्य स्थायाधिकारि उन व्यक्तियों में से हो जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के स्थायाधिकारि हैं या रह चुके हैं। यथास्थिति, मध्यस्थों या नियन्यक का विनिश्चय अनियम और प्रधानकारों पर प्रावृद्धकर होगा और उनके द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

III(3) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों में गुजरात के लिए अर्जित या उनको हस्तानित सभी भूमि की

प्रावृत्ति भव्य पदेश और महाराष्ट्र का भुगतान संहिताओं के अनुभार भू-राजस्व देगा।

III(4) गुजरात, ऐसे जिस प्रावृत्ति या निर्वासित स्मारकों, पुरागत्वावधि व्यक्तियों, भूजा के धार्मिक स्थान पर मूलियों को, जिनके सरदार सरोवर के प्रश्नांत जनपालन के कारण विवाचित होने की समावना है, हटाने या पुनर्वित के प्रयोगन के लिए मध्य प्रदेश और गहाराघूर द्वारा किए गए सभी खबरों, प्रभारों और व्यवसा का भुगतान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को करेगा और ऐसा भुगतान भार दिए जाने की वज्रा में, जलपालन द्वारा प्रवालित होने पर उनको जावत ऐसे किसी पूर्वक प्रतिकर का, जिसका उत्तरव्य होने इसके पूर्व किया गया था, भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

III(5) गुजरात निर्वासित व्यक्तियों द्वारा निर्वासित कुटुम्बों के उनके आवेदन खेत्रों में पुनर्वित के लिए इसमें इसके आवेदन अनुस्तविष्ट नियमों के अनुनाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनके द्वारा किए जाने कावै व्यवसी खबरों, प्रभारों और व्यवसा का भुगतान करेगा।

III(6) गुजरात, भूमि अर्जन और पुनर्वास और अन्य ऐसे विसामों के जिन्हें अन्यत्र के लिए जिन्हें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे अर्जन और पुनर्वास के प्रयोगन के लिए आवश्यक गम्भीर, स्थान प्रभार मध्य प्रदेश और गहाराघूर के बीच का उनको भुगतान जारीगा।

उपखण्ड IV : पुनर्वास के लिए उपचाल

IV(1) वर्तमान प्राक्कनन के अनुसार निर्वासित कुटुम्बों की संख्या मध्य प्रदेश के 158 ग्रामों में 6147 और महाराष्ट्र के 27 ग्रामों में 456 होगी। गुजरात उन कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए जो गुजरात में प्रधान करना चाहते हैं, इसमें ग्रामों वर्जित प्रभारों पर सरदार परियोजनों के विवरण और में, गुजरात में पुनर्वास ग्रामों की स्थापना करेगा। उन नियमित कुटुम्बों के लिए जो गुजरात में प्रधान नहीं करना चाहते हैं, गुजरात इसमें ग्रामों वर्जित प्रभारों पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनके आवेदन राज्य खेत्रों में ऐसे ग्रामों की स्थापना के लिए व्यवसी, प्रभार और व्यवसा करेगा।

IV(2)(i) वर्तमान प्राक्कनन के अनुसार ग्राम 106.68 मीटर (ग्राम 350फूट) के नीचे निर्वासित कुटुम्बों को संख्या, मध्य प्रदेश के 20 ग्रामों में 30 होगी और महाराष्ट्र के 20 ग्रामों में 250 होगी। राजपत्र में अधिकरण के विनिश्चय के प्रकाशन से छह मास के भीतर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ग्रामों परामर्श से, ग्राम 106.68 मीटर (ग्राम 350फूट) से नीचे के खेत्रों के निर्वासित व्यक्तियों के गुजरात में पुनर्वास के लिए एक या दो पुनर्वास ग्रामों के लिए स्थान नया फैलें। गुजरात पुनर्वास ग्रामों के लिए आवश्यक भूमि अर्जन करेगा और अधिकरण के विनिश्चय से वो वर्ष के भीतर उसे उपनिवास कराएगा। गुजरात में पुनर्वास ग्रामों के स्थानों के विनिश्चय में छह मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ग्राम 106.68 मीटर (ग्राम 350फूट) से नीचे के खेत्रों से गुजरात में प्रधान करने के इच्छुक नियमित कुटुम्बों की संख्या गुजरात का सूचित करेंगे। शेष निर्वासित कुटुम्बों के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ग्रामों में पुनर्वास के लिए भूमि वर्जित करने की व्यवस्था करेंगे।

IV(2)(ii) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, भूमि अर्जन और नियमित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त स्थानों की स्थापना करेगा। अधिकरण के विनिश्चय से तीन मास के भीतर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रभारीक के पास, उन राज्यों में स्थापन और पुनर्वास के वर्ष के लिए दो लाव जापे जाएंगा किसका नियमित व्यवसीजन वास्तविक वर्ष के भवधारण के पश्चात लिया जा गकेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अधिकरण के विनिश्चय से छह मास के भीतर ग्राम 106.68 मीटर (ग्राम 350फूट) नीचे के खेत्रों के लिए भूमि अर्जन कार्यान्वयन स्थापित करेंगे और अधिकरण के विनिश्चय से तीन वर्ष के भीतर भूमि, गुजरात

का परिवाजना प्रवोडरों के लिए इस्तेसित कर देंगे। अधिकरण के विनियम से 18 मास के भीतर, गुजरात भूमि के प्रतिकर हेतु मध्य प्रदेश को 70 लाख रुपये और महाराष्ट्र को 100 लाख रुपये अधिम देंगे, जिसे वास्तविक बचते के अवधारण के पश्चात् भासायेंजित किया जाएगा।

IV(2)(iii) आर एल 106.68 मीटर (आर एल + 350 फुट) से ऊपर के भेत्रों से निर्वासित कुटुम्बों के संबंध में गुजरात, गजपत में अधिकरण के विनियम के प्रकाशन से छह मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उन पुनर्वास प्राप्तों की संख्या और साधारण अवस्थिति का सूचना देंगा जिनके अधिकरण के विनियम के अनुसार गुजरात द्वारा स्थापित किए जाने की प्रस्तावना है गुजरात की प्रस्तावना की प्राप्ति से एक वर्ष के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों गुजरात को गुजरात में प्रवास करने के इच्छुक निर्वासित कुटुम्बों की संख्या सूचित करेंगे। तीनों राज्य प्राप्ति में विचार विमर्श करके, अधिकरण के विनियम से दो वर्ष के भीतर, गुजरात द्वारा अपने ही राज्य भेत्र में स्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित पुनर्वास प्राप्तों की संख्या और साधारण अवस्थिति का अवधारण करेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे ग्रामों की संख्या गुजरात को बताएंगे जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले हैं और जिनके लिए गुजरात को कमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भूमिका करना होगा।

IV(2)(iv) गुजरात जनसाक्षम के एक वर्ष पहले प्रत्येक पश्चात्वानी प्रक्रम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उन निर्वासित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए जो गुजरात में प्रवास के लिए इच्छुक हैं, विचार योग्य भूमि और भवन स्थिति अंजित करेंगा और उन्हें उपलब्ध करेंगा। गुजरात निर्वासित व्यक्तियों को पहले अपने राज्यभौत में पुनर्वासित करने की प्रस्तावना करेंगा।

IV(3) गुजरात निर्वासित व्यक्तियों की निम्नलिखित घनुवानों और सुख-सुविधाओं का भी उपलब्ध करेगा:—

(क) फिर से बसाने के लिए घनुवान (पुनर्वास घनुवान)—गुजरात प्रत्येक कुटुम्ब 750 रु. की राशि जिसमें परिवहन प्रभार भी सम्मिलित है, पुनर्वास घनुवान के रूप में देगा।

(ख) सहायता घनुवान—इसके प्रतिरक्षित, गुजरात निम्नलिखित मापान के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब को सहायता घनुवान देगा:

जहां कुल प्राप्त प्रतिकर	सहायता घनुवान
2000 रु. से ऊपर है	कुछ नहीं
2000 रु. और 5000 रु.	500 रु. जिसमें से उत्तमी रकम घटा दी के बीच है
500 रु. से कम है	500 रु.

(ग) नागरिक सुख-सुविधाएँ:

1. 100 कुटुम्बों के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय (3 कमरे वाला)
2. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक पंचायत घर
3. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक शौचालय
4. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक बीज भंडार
5. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक घाल उद्यान
6. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक घाम पोखर
7. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए, नालीसहित एक नेयजल कुंभा
8. प्रत्येक कालीनी समुचित स्तर की मड़कों द्वारा मुख्य सड़क से

मुक्ती होनी चाहिए

9. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए, एक चमुतरा

10. प्रत्येक निर्वासित कुटुम्ब एक मकान की जगह घरांत 18.39 × 27.43 मी० (60' × 90') माप का एक भूखण्ड—

निश्चुक पाने का हकदार होंगा और उसे वह आवंटित किया जाएगा। इसके अधारावा, गुजरात, नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए सड़कों, गरकारी भवनों, कुनै स्थानों प्रावित के लिए 302- अनिरिक्त भेत्र की व्यवस्था करेगा।

11. गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए, निम्नलिखित व्यवस्थाएँ करेगा:—

	रुपए
(क) पुनर्वास	750 प्रति कुटुम्ब
(ख) सहायता घनुवान	500 प्रति कुटुम्ब
(ग) प्रवासित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए भू-मर्जन	जो प्रति 6 कुटुम्ब 0.40 हेक्टर (एक एकड़ी) की वर में किया जाएगा
	1500 प्रति एकड़ी
(घ) नागरिक सुविधाएँ:	
1. 100 कुटुम्बों पर एक प्राथमिक विद्यालय	प्रति विद्यालय 30,000
2. 500 कुटुम्बों पर एक तामुदायिक हाल एवं पंचायत भवन	प्रति भवन 20,000
3. 500 कुटुम्बों पर एक चिकित्सालय	प्रति चिकित्सालय 25,000
4. 500 कुटुम्बों पर एक बीज भंडार	प्रति भंडार 10,000
5. 500 कुटुम्बों पर एक वाल उद्यान	प्रति उद्यान 6,000
6. 50 कुटुम्बों पर नाली सहित एक कुंभा	प्रति कुंभा 10,000
7. 500 कुटुम्बों पर एक तालाब	प्रति तालाब 20,000
8. 50 कुटुम्बों पर एक आयावार चबूतरा	प्रति चबूतरा 1,500
9. 100 कुटुम्बों पर एक प्राथमिक पूजा-स्थल	प्रति पूजास्थल 1,000
10. प्रति नई प्राचारी के लिए 3 किं०मी० के हिसाब से पहुंच मार्गों प्रावित संरक्षक मार्गों का विनिर्माण	प्रति किं०मी० 30,000
11. विवृत वितरण लाइन, घर गलियों में रोशनी, प्रति 100 कुटुम्ब 2 किं०मी०	प्रति किं०मी० 11,000
12. जलपान के अधीन आने वाले प्रत्येक नगरीय कस्बे के लिए सामाजिक सुविधाएँ, जैसे, जल प्रवाय और सकारी सुविधाओं का अभिन्यास और समतलन प्रावित	प्रति कस्बा 5,00,000

IV(4)(i) गुजरात को निवेश किया जाता है कि वह अपने भूमि प्रतिकर और पुनर्वास के प्राक्कलन में, इसमें पूर्व उप व्याप्ति IV(3) में अंतर्विष्ट निवेशों के अनुसार पुनर्वास और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करे।

IV(4)(ii) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के होने हुए भी गुजरात, सावेजनिक सम्पर्कों की हानि या दीने के पानी के कुओं, प्राथमिक विद्यालय भवनों, भीतरी मड़कों, प्राप्त्य स्थलों, पहुंच मार्गों, चिकित्सालयों, पंचायत भवनों, ग्रामीण विद्ययोग्य, राजमार्गों, कलों, टेलीप्राक लाइनों, यक्षित लाइनों आदि जैसी सुविधाओं या प्राविधिकों की हानि के लिए प्रतिवर का संदर्भ करने का बाधी नहीं होगा, किन्तु यह तब जब उसके स्थान पर मैकास्टिक संपर्क, सुविधाओं या प्राविधिकों की व्यवस्था सरवार सरोबर परियोजना की जानी है। उन प्रकारों को जिनके लि-

मुविधाएं हैं, यह विकल्प प्राप्त होना कि वे विद्यमान मुविधाओं के लिए प्रतिकर ग्रहण करने या गुजरात के व्यय पर उसे प्रतिस्थापित या स्थानान्तरित करा ले।

IV(5). यदृ स्पष्ट किया जाना है कि खण्ड IV(3)(ग) के प्रधीनीय मूल्य, वास्तविक पुनर्वासि के समय परिवर्तित हो सकते हैं। यदि परिवर्तित मूल्यांकन के संबंध में कोई विवाद या मनवेत्र उत्पन्न होता है तो मामले का अवधारण भाष्यस्थम द्वारा, ऊपर खण्ड III(2) में विहित रीति में, किया जाएगा और तबनुमार गुजरात के वायिक्र में भी परिवर्तन हो जाएगा।

IV(6)(i) निष्कासित व्यक्तियों को पुनर्वास देने में गुजरात के प्रकाशन होने की दशा में, या निष्कासित व्यक्ति, गुजरात द्वारा प्रदान किए गए बोक्स में बसना न आहते हो तो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर खण्ड IV(1) से (4) में उल्लिखित रीति में पुनर्वासि, नागरिक मुविधाओं आदि की व्यवस्था करेंगे। ऐसी दशा में गुजरात ने भी सभी व्यय, खर्च भावि देने के लिए दाती होगा जो उस दण में गुजरात ने भी सभी व्ययों, खर्चों आदि के संबंध के लिए दाती होगा जो मिष्कासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वासि और नागरिक मुविधाओं की व्यवस्था करने के सबबंध में हो इसके अन्तर्गत, निष्कासित व्यक्तियों को छोड़ी दरने या आवास के लिए आवंटित भूमि के अर्जन के लिए की गई कार्यवाही का खर्च और भू अर्जन अधिनियम के अनुसार दिए गए प्रतिकर की रकम भी है।

IV(6)(ii) : मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कोई भी बोक्स सरकार मरोबर के अधीन नक नक उल्लिखित नहीं किया जाएगा जब नक कि नमस्त भूमि और सम्पत्ति के अर्जन के लिए दिए गए सभी प्रतिकर, किए गए सभी व्यय और नागर नक का संबंध नहीं कर दिया जाना और वहाँ के निष्कासितों के पुनर्वासि की व्यवस्था इन निदेशों के अनुसार कर के निष्कासितों को सुचित नहीं कर दिया जाता।

IV(7) : कृषि भूमि का आवंटन — गोप्य प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब, जिसकी 25 प्रतिशत से प्रधिक भू-धूति वर्जित कर ली जाती है, सम्बद्ध राज्य में विहित अधिकारित भूमि सीमा और प्रति कुटुम्ब कम से कम 2 हेक्टर (5 एकड़) की सीमा के प्रधीन रहते हुए, अर्जित भूमि के बराबर लिखित भूमि आवंटित किए जाने का हक्कार होगा। और मिकाई की मुविधाएं उस राज्य द्वारा दी जाएंगी जिसके राज्य-क्षेत्र के भीतर आवंटित खेत्र लिखित हैं यह भूमि विस्थापित कुटुम्ब को, यदि वह जाहे तो, प्रतिसित कर दी जाएगी। उस के लिए प्रभारित कीमत वह होगी जो गुजरात और सम्बद्ध राज्य के बीच तथ की जाएगी। भूमि के लिए मंदल की जाने जाती कीमत में से, विस्थापित कुटुम्ब को अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में उसे दी जाने वाली रकम का 50 प्रतिशत, संदाय की आरम्भिक किस्त के रूप में, मुजरा कर दिया जाएगा। आवंटित भूमि की अतिरिक्त रकम आवंटिती से 20 वार्षिक किस्तों में व्याज रहित रूप में, वसूल की जाएगी। यदि भूमि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में आवंटित की जाती है। और गुजरात उसके लिए भुगतान कर देता है, वेश्वार खण्ड IV(6)(1), तो आवंटित भूमि के लिए सभी वसूलियां गुजरात के खाते में जमा की जाएंगी।

IV(8) : यदि इन निदेशों के खण्ड IV(1) से (7) तक की बाबत राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह इन निदेशों के खण्ड III(2) में विहित रीति में भाष्यस्थम के लिए निष्कासित किया जाएगा। भाष्यस्थम और वही उसे तय करेगा।

उपखण्ड V: गुजरात द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को किए जाने वाले संबंध का कार्यक्रम :

V(1) : गुजरात, अधिकरण का विनियम, राजनव में प्रकाशित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र सरकार मरोबर परियोजना के लिए अधिकरण द्वारा यथा स्वीकृत उपर्योग ख-भूमि का एक नया प्राक्कलन, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि अर्जन की लागत और विस्थापित कुटुम्बों के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वासि की लागत भी होगी, तैयार करेगा और मध्य पश्च प्रकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा।

V(2)(i) अधिकरण का विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् यथा भाष्य शीघ्र और प्रत्येक दशा में, उसके पश्चात् से तीन मास के अन्तराल में पूर्ण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा, गुप्रशासि को प्राप्त-अपने सीमा खेत के उन सभी तालुकों के जो भागत: या पूर्णत सरकार सरकार में जलालावित हो सकते हैं, मजमूली/तालुका नक्शों के तीन-तीन मेट्रोडेरों। ये नक्शे शाम की सीमा उपर्योग करेंगे। गुजरात, मजमूली/तालुका नक्शों की प्राप्ति के पश्चात् से तीन मास के भीतर, उन पर एफ० आर० एल० में नीचे के खेतों को आर० एफ० आर० एल० भाषा एम० डब्ल्य० एल० के बीच के खेतों को, जिनके अन्तर्गत पश्चात् से प्रभावित खेत भी हैं, चिन्हांकित करेगा और इस प्रकार विनियमित करने के पश्चात् एक-एक मेट्रोडेर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बास सकता है।

V(2)(ii) : पूर्णकांत रूप में विनियमित मजमूली/तालुका नक्शों का एक मेट्रोडेर वापस पाने के पश्चात् यथा भाष्य शीघ्र और प्रत्येक दशा में उससे छठ मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रधिसूचनाएं प्रकाशित करेंगी जिनमें यह अधिसूचित किया जाएगा कि उनके सीमा खेत के भीतर एफ० आर० एल० से नीचे स्थित भूमि और एफ० आर० एल०, तथा एम० डब्ल्य० एल० के बीच स्थित भवनों पार्केस्थ भूमि नहिं, और जो एम० डब्ल्य० एल० के परिणाम स्वरूप पश्चात् से प्रभावित है (अधिसूचना में विनियमित किया जाए), की सरकार सरकार भवियत करने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है।

V(2)(iii) : यथापूर्वोक्त राजपत्र में अधिकरण के विनियम के प्रकाशन के पश्चात् यथा साध्यतीय, और प्रत्येक दशा में उससे एक बर्ष के भीतर गुजरात, बांध के सन्निमाण के वार्षिक कार्य-क्रम की सूचना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देगा।

V(2)(iv) : अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित भूमि के प्रस्तावित अर्जन के विस्तृ प्राप्ति कीमती भुवाई की जाएगी और उसे निष्टाया जाएगा और अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित कोई रिपोर्ट राज्य सरकार की शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारें अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपेक्षित अधिसूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र और प्रत्येक दशा में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अपनी-अपनी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से सीत बर्ष के विवासान से पूर्व, जारी करेंगी।

V(2)(v) : गुजरात से सरदार सरोबर बांध के सन्निमाण का वार्षिक कार्य-क्रम प्राप्त होने पर, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के परामर्श से, यथा साध्य यी-प्र अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर भूमि के अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनियमिय तैयारी और अधिनियम की धारा 16 से शीघ्र भूमि का कार्यर मौने के प्रक्रम तक के कार्य-क्रम को अनिम रूप देंगे।

V(3)(i) : गुजरात से अपेक्षा की जाती है कि यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, उनके द्वारा अनिवार्यतः अर्जित की गई ऐसी भूमि के लिए, जो गुजरात को दी जारी है, प्रतिकर का और गुजरात को दी जाने वाली सरकारी भूमि के बाजार मूल्य का, संदाय करे और ऐसे व्यय का भी संदाय करे जो इसमें इससे पहले उपबरित रूप में निष्कासित कुटुम्बों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वासित करने के संबंध में उपगत किया जाना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक बर्ष 30 सिन्मवर की या उससे पूर्व गुजरात को वह रकम सूचित करेंगे जो गुजरात द्वारा कमश्श: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संदर्भ की जानी है। ऐसी रकम सूचित करने से समय निम्नलिखित को छाना में रखेंगे, संपत्ति—(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उम का विस्तार जिसकी बाबत अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनियमिय किए जाने हैं।

(क) उम का सरकारी भूमि का विस्तार अगले दिन बर्ष में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा गुजरात को दी जानी है।

(ग) निष्कासित कुटुम्बों के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वासि की बाबत अगले दिन बर्ष के दौरान उनके पुनर्वास पर मध्य प्रदेश

और महाराष्ट्र द्वारा किया जाने वाला था। शरणे विस वर्ष के लिए इन प्राक्तिकों को नैतर करने में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उस गतिर को हिंमाव में ले ले जो गुजरात द्वारा इन घटकों के अनुसरण में चालू बिल वर्दे में किए गए मंदिर और बस्तुः उक्त वित वर्दे में मंदिर राम के बीच हैं।

V (3) (ii): इन प्राक्तिकों के आधार पर गुजरात, डायली हिन्द वर्दे के 31 मर्ह की या उन से पूर्व कारण खण्ड V (3) (i) में यथा उपर्याप्त प्राक्तिक रकम का गलाय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दर देगा।

V (3) (iii): गुजरात, जलपालन के प्रयोग उत्तरवर्ती प्रकम पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जलपालन के अधीन आने वाले क्षेत्र की सूचना, कम गे कम 18 माल पूर्व देंगा। जलपालन के संबंधित प्रतिम के अधीन आने वाले अंत्र के लिए नींवि, संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित की जाने वाली ऐसी नारीख वर्दे जो जलपालन की नारीख से छठे यांत्र में कम पूर्व की रही होंगी, अपनी गंभीर को अधिसूचित में लिए या उपर्योग करने के लक्ष्यात होंगे और ऐसे अधिसूचित या उपर्योग के लिए उन्हें कुछ नहीं देना द्वारा। उन्हें अधिसूचित वार्ताख सक देना चाही अवश्य कर देना होगा।

V (4) (i): गुजरात द्वारा प्रतिवर्ष अनिवार्यः अजित खीं गई पूर्वोन्नति भूमि के लिए गतिवर्ष प्रतिकर खीं रकम का मंदिर कर दिए जाने पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीघ्रान्तिरी शीर्जन पूरा करें और वह भूमि गुजरात को अंतरित कर देंगे जिससे कि वह भूमि, इन निवेशों के खण्ड V (5) से (8) तक के अधीन रहने हुए केवल जलपालन के प्रयोग जाएगा।

V (4) (ii): इस में इसमें पूर्व उपर्याप्त रूप में गुजरात द्वारा आवारी भूमि का आवार मूल्य संश्लेषण वर्दे दिए जाने पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा भारत मंष ऐसी भूमि गुजरात को सौप देंगे, जिसे जिससे कि वह भूमि, इस निवेशों के खण्ड V (5) से (8) तक के अधीन रहने हुए केवल जलपालन के प्रयोग गुजरात में निहित हो जाए।

(5) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तत्संबंधी भूमि राजस्व संहिताओं के अनुतार गुजरात के लिए अजित या उसे हस्तान्तरित तत्संबंधी राज्यसेवों में भूमि के लिए प्रतिवर्ष सौप भू-राज्यव भी रकम, कमणः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समय-समय पर विद्यमान वर्दों से, संक्षय करेगा।

(6) यथास्थिति, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात को प्रत्येक वर्ष ऐसा कोई राजस्व जो उन भूमियों पर खेती वर्दों से प्राप्त हो, जो सरदार सरोवर में कार्यक्रमः उच्छव द्वारा जाए, उसमें से उत्तरक संग्रहण प्रपत्रों की कटीती करने के पश्चात्, प्रियेति करेगा।

(7) जलपालन के अधीन आने वाली भूमि के गुजरात में निहित हो जाने पर भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जलपालन क्षेत्र पर अपनेअपने राज्य में अपनी संप्रभुत के अधिकार का प्रयोग करने रहेंगे।

(8) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कमणः अपनी-अपनी जल प्लानित भूमि पर, छील के एक भाग में मछलों पकड़ने, नौवालन और जल परिवहन के अधिकारों का अन्यन्य रूप से प्रयोग करने के हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकार का प्रयोग सरदार सरोवर परियोजना की किसी उपर्योगित, पर अतिकूल प्रक्षाव न जाने या परियोजना कामिको के विधिपूर्ण कर्तव्यों के विवरन में व्यवधान उत्पन्न न करे।

(9) जल प्लानित के अधीन आने वाली भूमि के ऐसे प्रविष्टि अधिकार जो विनिर्दिष्ट रूप से गुजरात को अंतरित नहीं किए गए हैं, उस सरकार में निहित वर्दे रहेंगे जिनके भीमा शेष में वे भित्ति हैं।

V (10): उक्त भूमि के जलपालन के प्रयोगजन के लिए, जिसके लिए उसे अजित किया गया है, उपर्योग न किए जाने की दशा में, गुजरा-

त राज्य यथास्थिति, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र को ऐसी भूमि इन वर्दों के अधीन रहने हुए पुनः अन्तरित कर देगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसी भूमि की आवश्यकता निवापन प्रसिद्ध कर रहा कर देंगे।

V (11): यदि निर्वाचित कुटुम्बों के पुनर्वासि के लिए अजित किसी भूमि का उपयोग उन प्रयोगजन के लिए सही किया जाता है तो उसी संभवा है, संदात जिए आने पर उसे नूतन स्थानों को लोडा दिया जायगा या अन्यथा निवापा दिया जाएगा और प्राप्ति गुजरात के आवश्यक जमा दर्ता जाएगी।

V (12): सरदार सरोवर की आवश्यकता भूमि प्रतिवर्ष करने और निर्धारित विकासों के पुनर्वासि पर गुजरात द्वारा किए गए मध्योच्च वर्दे, सरदार सरोवर परियोजना प्रक्रियात, यूनिट 1 आवश्यक और अनुसंदर्भ संकर्म पर प्रभारित किया जाएगा।

उपर्योग VI: यदि सभी पत्रहार राज्य के द्वारा सभी पूर्ववर्ती खण्डों था उसमें से किसी में कोई परेवर्ती, संतोषित और उपास्तरण करने हैं तो खण्ड XI को कोई वात उसे निवारित नहीं करेगी।

उपर्योग XII: सरदार सरोवर परियोजना के खर्च का सिवाई और शक्ति विभाग के बीच आवंटन

इस अवधारित करने हैं कि यूनिट 1-आवश्यक और अनुसंदर्भ संकर्म का वर्दे मिलाई और शक्ति विभाग के बीच निम्नानुसार बांटा जाएगा—

मिलाई विभाग

43.9 प्रतिशत

शक्ति विभाग

56.1 प्रतिशत

उपर्योग XIII: सरदार सरोवर परियोजना के खर्च के सिवाई भूमि विभाग के बीच आवंटन

(क) (1) सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट 1 (बांध और अनुसंदर्भ संकर्म) के खर्च में सिवाई भाग को गुजरात और राजस्वान के बीच 18:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(क) (ii) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आने वाले वर्दों में प्रयोग के लिए सरदार सरोवर से लिए जाने वाले जल के लिए सरदार सरोवर वाध की लागत के सिवाई संघटक और उसके प्रबलान और वाधिक अनुरक्षण के आनुपातिक अंश का भी अभियाप्त करेगा। अनुपातिक अंश 9.5 प्रति ०५० प्रति ०५० में से लिए जाने वाले वस की मात्रा के अनुपात में होगा। इस प्रकार अभियाप्त की जाने वाली रकम, गुजरात और राजस्वान के खर्च में 18:1 के अनुपात में जमा की जाएगी।

(क) नमेदा विवरण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नवगांव नहर और उसके डिजाइन की लागत दोनों राज्यों द्वारा निम्नलिखित रूप में बांटी जाएंगी :

(i) गुजरात द्वारा प्रस्तावित रेकिल्प्ट के लिए भूमि शुरू कार्य और लाइनिंग की बाबत लागत अन्तर अन्तर और जो अब विविध हैं, पूरी रूप से गुजरात वहन करेगा।

(ii) नहर की वास्तविक लागत से कार (i) की कम करके जो जाएगा, वह क्षूसेक मील के आधार पर बांटा जाएगा।

वास्तविक लागत को गुजरात और राजस्वान के बीच पहले क्षूसेक माल आधार पर बांटा जाएगा और कार्य समाप्त हो जाने पर लागत का अंश ऊपर बांटे गए अनुपात समाप्तित किया जाएगा। राजस्वान अपने हिस्से की लागत प्रति खर्च बजट आवंटन के आधार पर जमा करेगा। इसे बांट में खर्च के अन्त में वास्तविक खर्च के अनुपात समाप्तित किया जाएगा। अनुरक्षण पर समिरण के पश्चात् खर्च को सक्षिमण के रूप में नहीं माना जाएगा।

यदि लागत बांटने के प्रयोजनार्थ नवगांव मध्य पर लागत खर्च के आंकड़ों पर राजस्वान और गुजरात के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो विचार नमेदा विवरण प्राधिकरण को निर्वेशित किया जाएगा और ऐसे निर्वेश पर उसका विनियोग अंतिम और आकर्षक होगा।

वाण 14: प्राधिकरण के विनियोग को कियान्वित करने के लिए तंत्र की स्थापना

हम, प्राधिकरण के विनियोग को कियान्वित करने के लिए तंत्र की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

उपचाण्ड 1: प्राधिकरण का गठन

1(1) नर्मदा जल विद्युत अधिकरण (जिसे इसमें आगे आदेश कहा गया है) के विनियोगों और नियंत्रणों के पालन प्रीति त्रियान्यन्यन को सुनियोगित करने के प्रयोजन के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जिसे इसमें आगे प्राधिकरण कहा गया है) नामक एक अंतरराज्यिक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।

1(2) प्राधिकरण में सात उच्च पंक्ति के इंजीनियर होंगे, जिनमें से हर एक रिक्वार्ड विभाग, प्राक्षिक विभाग या राज्य विद्युत बोर्ड का प्रमुख इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर या अपर मुख्य इंजीनियर होगा और जिन्हें मध्य प्रवेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीन अन्य प्रधायक इंजीनियर होंगे, जो मुख्य इंजीनियर से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे और जिन्हें केन्द्रीय सरकार पक्षकार राज्यों से प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिष्ठि किया जाएगा। उसे उन प्रधिवेशनों में, जहां एक से प्रधिक राज्यों के हित पर प्रभाव द्वाले वाले विषयों पर विनियोग किया जाता हो, विमर्शी मद प्राप्त होगा और वह प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्य का भाग साधक होगा। यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसे किसी सदस्य को, जो उसकी राय में सदस्य के रूप में जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकरण से हटाने या नियन्वित करने की शक्ति होगी।

1(3) प्रथम स्वतन्त्र सदस्य पूर्ण कालिक सदस्य होगा और प्राधिक से प्रधिक पांच वर्ष की प्रवधि के लिए नियुक्त किया जायगा। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सदस्य अंश-कालिक सदस्य होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी हो, यथास्थिति, स्वतन्त्र सदस्य या अंशकालिक सदस्य के लिए नियुक्ति के निवन्धन और शार्तें अवधारित करेगा। प्राधिकरण के सात सदस्यों का प्रथम नियुक्ति, प्रधिकरण के विनियोग के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से यथासाध्य तीन मास के भीतर कर दी जाएगी।

1(4) सदस्यों के रिक्त स्थान

यदि तीन स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी का स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और स्वतन्त्र सदस्यों से भिन्न चार मदस्यों में से कोई स्थान रिक्त हो जाने पर, राज्य सरकार जिसके द्वारा वह सदस्य जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त किया गया था, उक्त रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगो।

किसी सदस्य की बीमारी या किसी भी कारण अनुपस्थिति की वजा में, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार (यथास्थिति), जिसके द्वारा वह नियुक्त किया था, ऐसी बीमारी या अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति को राजनायक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती और ऐसे स्थानापन्न सदस्य को इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करते हुए, उस सदस्य की (देखिए उपचाण्ड 5) जिसके बासे में वह इस प्रकार कृत्याली है, सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अगला अंगठ स्वतन्त्र सदस्य, न कि स्थानापन्न सदस्य प्राधिकरण के कारबाही प्रधिवेशनों में अध्यक्ष के रूप में या प्राधिकरण के अध्यक्ष के बीमार होने या अनुपस्थित होने की वजा में, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेगा।

उपचाण्ड 2: प्राधिकरण का सचिवः

प्राधिकरण एक सचिव नियोजित करेगा जो इंजीनियर होगा। वह प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

उपचाण्ड 3: गणपूति और मतदान

प्राधिकरण के ऐसे कारबाहर के सिवाय जिसे प्राधिकरण नेमी रूप में समय-समय पर विहित करे सभी अन्य कारबाहर के संबंधहार के लिए गणपूति पांच मदस्यों से होंगी और बहुमत की भवगति आवश्यक होंगी। प्राधिकरण ऐसे किसी कारबाहर को, जिसमें किन्हीं दो राज्यों के हितों में विरोध होने की संभावना हो, नेमी के रूप में विहित नहीं करेगा। नेमी कारबाहर के संबंधहार के लिए सीन सदस्यों से गणपूति होगी और प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, प्रधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष की विमर्शी मत प्राप्त होगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में उसे नियांयक भत भी प्राप्त होगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए मदस्यों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी।

उपचाण्ड 4: प्राधिकरण द्वारा कार्य का नियन्दन

4(1) नीचे उपचाण्ड 4(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी अपने समक्ष कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा या प्रधिवेशन बुलाकर कर सकेगा। तथापि, प्राधिकरण का कोई सदस्य यह अपेक्षा कर सकेगा कि अमुक कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा न करके प्रधिवेशन में किया जाए।

4(2) प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर अपना विनियोग किती अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों के सदस्य उपरित्थित हों, संकल्प द्वारा अभिवित करेगा:—

(1) कारबाहर संबंधी नियमों की रचना;

प्राधिकरण के किसी सदस्य या सचिव अध्यक्ष किसी पक्षाधिकारी की हक्कों का प्रत्यायोजन;

(3) प्राधिकरण के कारबाहर के किसी भाग का श्रीपत्रारिक या नेमा प्रकृति के कारबाहर के रूप में वर्गीकरण;

(4) कोई अन्य ऐसा विषय जिसके विनियोग की बाबत चार पक्षकार राज्यों में से कोई यह अपेक्षा करे कि वह किसी ऐसे अधिवेशन में किया जाए जिसमें पक्षकार राज्यों के सभी सदस्य उपरित्थित हों।

किन्तु यदि इस उपचाण्ड के अधीन किसी विणिष्ठ मद का दो क्रमबद्धी दृढ़कों में पक्षकार—राज्यों में से किसी एक या प्रधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो उसका निपटारा उपचाण्ड 14 के उपचाण्ड 3 के अधीन किया जायगा।

4(3) पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण अपने कारबाहर के संबालन के लिए अपने नियम बनाएगा।

4(4) प्राधिकरण, अपनी समस्त कार्यवाहियों का समुचित कार्यवृत्त या अभिलेख स्थायी अभिलेख के रूप में रखाएगा।

उपचाण्ड 5: सदस्यों का परित्वान

निम्नलिखित से उत्तम हानि, क्षमि या तुकान के लिए प्राधिकरण का कार्य भा सदस्य, अधिवाहा या कर्वाचारी नहीं होगा, अर्थात्

(क) ऐसे मत्स्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सद्भावपूर्वक और जिन विदेश के स्पष्ट आदेश के प्राधिकार के अधीन की गई कोई कार्रवाई, भले ही वाद में ऐसी कार्रवाई को प्राधिकरण अवधारित कर दिया जाए, या

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियोजित और ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के अधीन सेवारत किसी अन्य अधिकार का उपेक्षण या दौषपूर्ण कार्य या सेवा, किन्तु यह तब जब कि ऐसा सदस्य अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे अन्य अधिकार की नियुक्ति में या उसके कार्य के पर्यावरण में सम्यक् सावधानी बरतने में असफल न रहा हो।

'उपलब्ध 6: प्राधिकरण के अधिकारी और सेवक

प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे और उन्हें उन नियमों और सेवकों को नियुक्त कर सकता है, जो वह ठोक समझे और उन्हें उन नियमों और विनियमों के अधीन सेवा से हटा सकता है या पदमृत कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, हटाए जाने या पदमृत किए जाने के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे सभी अधिकारी और सेवक एकमात्र प्राधिकरण के नियंत्रण में होंगे। वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होती हैं। उक्त चारों राज्यों की सेवा में नियोजित अधिकारियों की नियुक्ति या नियोजन प्राधिकरण उस अनुपात में कर सकेगा जो वह ठीक समझे। प्राविन्द्र राज्य सरकारों से ऐसी व्यवस्था करेगा कि वे राज्य सरकारों में नियोजित अधिकारियों को प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन के लिए या प्राधिकरण के लिए किसी कार्य या सेवा को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध करें। प्राधिकरण किसी भी अधिकारी को सेवा को संभालने और नियंत्रण के लिए उपलब्ध समझे, ऐसी अधिकारियों को अन्य स्रोत से, जो भी वह उपयुक्त समझे, ऐसा अधिकारियों को समझे।

'उपलब्ध 7: प्रशासनिक और फौजदारी संघर्ष

प्राधिकरण का समस्त व्यय (जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र सदस्यों के वेतन और व्यय भी हैं) मध्य प्रवेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य समान अंतर्गत में वहन करेंगे। किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य से संबंधित व्यय, सम्बद्ध राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। प्रथेक राज्य में गेझों और अन्य जनाय स्थानों के अनुरक्षण, प्रचालन और नियंत्रण का व्यवहार और आँकड़े संमूलित करने के लिए दूर संचार का व्यवहार सम्बद्ध सरकार वहन करेंगे।

भाइरों, शक्ति संस्थानों, मोड़ संकर्मी, गोर्ख संकर्मी और नहरों के सम्प्रभाव तथा अनुरक्षण का व्यवहार पूर्णतः उस राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए भी संकर्म स्थित हैं जहाँ इस प्रकार पूर्जी लागत आटो जाती है वहाँ प्रचालन और अनुरक्षण लागत भी उसी अनुपात में आटो जाएगी और लाभ में बढ़तारा होने की दशा में अन्य राज्यों के बीच उसे छाट दिया जाएगा।

(2) उन संकर्मों को छोड़कर जिनकी लागत दो या अधिक पश्चात राज्यों के बीच आठों का अधिकरण ने नियंत्रण दिया है।

'उपलब्ध 8: प्राधिकरण को शक्तियाँ, और कर्तव्य :

8(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्य समन्वय और नियंत्रण करता है। सामान्यतः सभी द्विपक्षीय विषयों का निपटारा सम्बद्ध राज्यों द्वारा मिल-कर करना आहिए और प्राधिकरण का तभी निर्दिष्ट किया जाना आहिए जब कोई विवाद हो।

8(2) प्राधिकरण की यह शक्ति और कर्तव्य होगा कि वह ऐसा कोई या सभी कार्य करें जो निम्नलिखित की व्याख्या द्वादेशों को सामूहिकरण करने के संबंध में आवश्यक, पर्याप्त या समीक्षित हैं, प्रथम् :-

- (i) नवदा जल का भण्डारण, बंटवारा, विनियम और नियन्त्रण;
- (ii) सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त शक्ति का बंटवारा;
- (iii) मध्य प्रवेश द्वारा जल का नियमित रूप से छोड़ा जाना;
- (iv) सम्बद्ध राज्य द्वारा सरदार सरोवर के अधीन जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्तियों का सरदार सरोवर परियोजना के लिए अर्जन;
- (v) निष्कासित व्यक्तियों को प्रतिकर, उनका पुनर्वास हथा व्यवस्थापन; और
- (vi) वर्च का बंटवारा।

8(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी छत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रयोग डाले जिना, प्राधिकरण अन्य छत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित छत्य भी करेगा :-

- (i) व्यास्तिति, मध्य प्रवेश या गुजरात प्राधिकरण को, सरदार सरोवर परियोजना रिपोर्ट, नवदा सागर परियोजना रिपोर्ट, आंकड़े और महेश्वर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण सम्बद्ध राज्यों, केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग को इन परियोजनाओं की ऐसी कोई विशिष्टता बताएगा जो प्राधिकरण के आवेदनों के क्रियात्वपन के प्रतिकूल हैं। कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन या बांध, विद्युत-गृहों और नहर शोर्ख संकर्मों को प्रमुख विशेषताओं या लागत में महत्वपूर्ण बृद्धि प्राधिकरण को सूचित की जाएगी जिससे कि प्राधिकरण उस संबंध में समुचित कार्रवाई कर सके।
- (ii) प्राधिकरण नियमों को उपलब्धता को व्याज में रखते हुए, नमदेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना का हस-उद्देश्य से चरण क्रम विनियमित करेगा और उनके समिरण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करेगा जिससे कि परियोजनाओं के समिरण कार्य के पूर्ण होने के दौरान और उसके पश्चात, समीक्षीय रूप में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (iii) प्राधिकरण, सम्बद्ध राज्यों से, कार्य और व्यय दोनों की व्याख्या कालिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना के विभिन्न एककों के समिरण को प्रगति का पुर्वविनायकत करेगा और जब भी आवश्यक हो, सम्बद्ध राज्य को एक I—बांध और अनुलग्न संकर्म तथा एक III—सरदार सरोवर परियोजना विद्युत काम्पलेक्स को छोड़कर ऐसे उपाय करने की मालाह देगा जिससे कि कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। राज्य परियोजनाओं के संबंध में, उपलब्ध 8(3)(i) के प्रनुपार प्राधिकरण को कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (iv) प्राधिकरण, जब भी आवश्यक हो, सम्बद्ध राज्यों को समुचित निवेश देगा कि वे, गुजरात राज्य के लिए सरदार सरोवर परियोजना में जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्ति प्रदित्त करने और तत्पश्चात वे गुजरात राज्य को उपलब्ध कराने और तद्विन निष्कासित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर और पुनर्वास के संबंध में न्यायाधिकरण के आवेदनों का समय से और पूर्णतः प्रनुपालन करें।

- (5) प्राधिकरण, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक से, जहाँ आवश्यक हो, स्वचालित अभिलिखितों से मुनिशित ऐते प्रवाह और अन्य गेज़ स्टेशन निकास, गाव और वालीकरण संप्रेषण स्टेशनों और आदेशों के उपचार्यों को पूरा करने के लिए भवित्व अभिलेख रखने के सिए समय-समय पर यथा आवश्यक माप-युक्तियों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबलत करवाएगा। यदि आवश्यक ममता जाए तो सम्बद्ध राज्य से मुख्य नहरों के छोर पर और नर्मदा नदी तंत्र से राजस्थान के लिए प्रवाहित जल को मात्रा के मापने के सिए नहर के उपनिकाम पर अनुमंडित किसी की माप युक्तियों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबलत कराएगा।
- (6) नर्मदा के बहाव का उत्त सभी स्टेशनों पर, जहाँ प्राधिकरण आवश्यक समझे, ममती अभिलेख रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों को सहसम्बद्ध किया जाएगा।
- (7) प्राधिकरण, इस रिपोर्ट के अध्याय II में दिए गए मार्गदर्शन के प्राधार पर जल के लेखा मंडंडी नियम या विनियम बनाएगा और जल के विनियमन और लेखा के प्रयोजन के लिए इस दिन की प्रवधि के लिए प्रत्येक राज्य के जल का हिस्सा प्रबलारित करेगा।
- (8) प्राधिकरण, निम्नलिखित की बाबत अधिकरण के आदेशों का क्रियान्वयन मुनिशित करेगा, अर्थात् :—
- (क) मध्य प्रदेश द्वारा नियमित रूप से छोड़ जाने वाले जल की मात्रा और स्वरूप;
- (ब) ऐसे नियमित जल प्रदाय के लिए संदाय/लागत का बटवारा।
- (9) प्राधिकरण सम्बद्ध राज्य से प्रत्येक मौसम में नर्मदा से सिवित देने का, नर्मदासागर पर और उसके अधीनस्थी जल विद्युत यांकित स्टेशनों में से प्रत्येक द्वारा उत्पादित शक्ति, घरेलू, नागरीय और औद्योगिक या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए बहुत और सर्वार सरोबर परियोजना से प्राप्त नदी में जाने वाले जल के आंकड़े एकत्र करेगा।
- (10) प्राधिकरण, नर्मदा या उसकी सहायक मादियों में किसी जल वर्ष (1 जुलाई से प्राप्त वर्ष के 30 जून तक) में बहने वाले पानी की मात्रा प्रबलारित करेगा।
- (11) प्राधिकरण समय-समय पर प्रत्येक राज्य, द्वारा अपने जलाशयों और अन्य भण्डारों में बंदरारित पानी की मात्रा प्रबलारित करेगा और उस प्रयोजन के लिये कोई भी युक्ति या पद्धति अपना सकेगा।
- (12) प्राधिकरण, राज्यों द्वारा या यथा आवश्यक उमर्मे से कुछ के द्वारा किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में तथा किसी भी समय नर्मदा नदी के जल के उपयोग को, समुचित कालिक प्रन्तरालों पर प्रबलारित कराएगा और इस प्रयोजन के लिये नर्मदा नदी में से या उसकी सहायक नदियों में से सभी विषयों या शक्तिवर्णों को, चाहे वे प्रहृत हों या कृतिम या भागतः प्राकृतिक हों और भागतः कृतिम, व्यान में लेगा और ऐसे उपयोग की ऐसी पद्धति से नापेगा जो वह ठीक समझे।
- (13) प्राधिकरण या सम्बद्ध रूप से प्राधिकृत उमर्मे किसी प्रतिनिधि को ऐसी किसी भूमि या सम्पत्ति पर प्रवेश करने की शक्ति हीनी जिस पर नर्मदा जल के प्रयोग के लिये किसी राज्य द्वारा किसी परियोजना या किसी परियोजना का विकास काय या जेंजिंग व्यापन या जलीय स्टेशन के किसी कार्य का या मापक युक्ति

का सन्निधान किया गया है या किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य अपने समुचित विभागों द्वारा प्राधिकरण को और इस निमित्त उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को पूर्ण सहयोग और सहायता देगा।

- (14) प्राधिकरण यथा आवश्यक रूप में अधिवेशन करता रहेगा और उनमें उचित जल अवधि स्थानी बाबत विनियम लेगा। इसके प्रन्तर्भूत, विशिष्टतः आदेशों के प्रनुसार नर्मदा नदी प्रणाली के जलाशयों ते जल की निकासी की रीत और व्यारे भी हैं। विशिष्टतः प्राधिकरण पारी भरण मौसम के प्रन्त में अधिवेशन करेगा और नर्मदा नदों प्रणाली के जलाशयों में जल की उपलब्धता का पुनर्विलोकन करेगा और पिछले भण्डार को व्यान में रखते हुए अगले सिवाई मौसम के लिये उनके विनियम के तरीके की बाबत विनियम लेगा।

- (15) प्राधिकरण, सरवार सरोबर से तीन राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की आवंटित शक्ति के अंशों की पूर्ति में शक्ति के उत्पादन और परेण्य के लिये सन्निधान के चरण बढ़ कार्यक्रम के लिये तथा उसके लिये संवार्यों के लिये प्राधिकरण के आदेशों के प्रनुसार निवेश देगा। प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरवार सरोबर प्रक्षेत्र में शक्ति का उत्पादन और परेण्य आदेशों के अनुसार हो रहा है।

- (16) प्राधिकरण, बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान और बाढ़ नियन्त्रण, जिसके अंतर्गत गंभीर प्रबलेपण और दूरसंचार पद्धतियाँ भी हैं, संबंधी कार्रार स्थापन, अनुरक्षण और प्रबलत के लिये समेवित निवेश जारी करेगा। किसी संरचना की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संरचना के भारतावधि मुख्य हजारिन्यर पर होगा और उस पर ऐसा कोई विनियम या आदेश आवश्यक करनहीं होगा जिसके उसकी राय में, ऐसी संरचना के सुरक्षा की खतरा हो सकता है। प्राधिकरण, बाढ़ों के दौरान जलाशयों के प्रचालन के बारे में प्रतिवर्ष आंकड़े प्रकाशित करेगा और वे पक्षकार राज्यों को उपलब्ध कराएगा।

- (4) प्राधिकरण, अपने अनुभव के आधार पर, एक संकल्प द्वारा उपरोक्त उपखण्ड 8(3)(1) से (16) तक में प्रणित कृत्यों में परिवर्तन या वृद्धि कर सकेगा।

- (5) सभी सम्बद्ध राज्य, प्राधिकरण की नर्मदा घाटी विकास से संबंधित और प्राधिकरण द्वारा मार्गी जाने वाली सभी सुवर्गत जानकारी शीघ्र और युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

उपखण्ड 9: प्राधिकरण की वार्तिक रिपोर्ट

- प्राधिकरण आरों राज्यों में से प्रत्यक्ष को, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में वर्तमान जल वर्ष (1 जुलाई, से 30 जून तक) की समाप्ति से पूर्व एक वार्तिक रिपोर्ट तैयार कराकर भेजेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण द्वारा किए गए क्रियाकलाप का उल्लेख होगा और प्रत्येक राज्य को, किसी भी समय उसकी प्रायोग कर, ऐसी कोई जानकारी, जो उसके पास है, उपलब्ध कराएगा और अपने अभिलेखों तक राज्यों और उनके प्रतिनिधियों को पहुँच होने देगा।

उपखण्ड 10: प्राधिकरण का अभिलेख और उसका स्थान

- प्राधिकरण सभी अधिवेशनों और कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा, नियमित लेखा रखेगा, और उसका एक ऐसा उपयुक्त कार्यालय होगा जहाँ दस्तावेज़, अभिलेख, लेखा और गोंग आंकड़े आरों राज्यों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा, ऐसे समयों पर और ऐसे विनियमों के प्रधीन जैसे प्राधिकरण प्रबलारित करे, निरीक्षण के लिये बहुते रहे।

नमंदा नियंत्रण प्राधिकरण के केन्द्रीय, प्रावेशिक और उप प्रावेशिक कार्यालयों का स्थान प्राधिकरण अवधारित करेगा।

प्राधिकरण के मुख्यालय, जब तक वह स्थायी अवस्थान का विनिष्टक्षय नहीं कर सकता, मई विली में होंगे।

उपलब्ध 11: संविदाएँ और करार

प्राधिकरण ऐसी संविदाएँ और करार करेगा जो उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हृत्यों के पूर्णतः और सम्पूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक और अनिवार्य हैं।

उपलब्ध 12: वित्तीय उपलब्ध

(1) प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूँजीगत और राजस्व व्यय मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य समान रूप से बहन करेंगे। चारों राज्यों की सरकारें, प्राधिकरण को उसके हृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूँजीगत और राजस्व व्यय के लिए निधि देंगी।

(2) प्राधिकरण के गठन के पश्चात् चारों राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार प्रारम्भ में, प्राधिकरण की निधि में 5,00,000 रु. (पाँच लाख रुपए) का अभिदाय करेगी।

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष सिन्हम्बर मास में, पहली प्रैल से प्रारम्भ होने वाले भागामी वर्ष के आरह मास के दीरान अपेक्षित धन राशि के अंतर्वार प्रावक्तव्य दैवतार करेगा। इन प्रावक्तव्यों में वह रीति दर्शन की जाएंगी, जिसमें देसा धन खर्च करने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण 15 घटकूबर को या उससे पूर्व, ऐसे अंतरे वार प्रावक्तव्य की एक-एक प्रति चारों राज्यों के सम्बद्ध मुद्रा इंजीनियरों को प्रेरित करेगा और उसमें वह राशि दर्शित करेगा जो भागामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अभिदाय के लिए प्रेरित है। प्रत्येक राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा दर्शित रूप में अपने अभिदाय का, प्राधिकरण को संदाय भागामी वर्ष के 30 प्रैल को या उससे पूर्व कर देगा।

(4) प्राधिकरण सभी प्राप्तियाँ और संवितरणों का अंतरा और सही लेखा रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और उसकी प्रतियोगी सम्बद्ध महालेखाकारों तथा चारों राज्यों के सम्बद्ध मुक्य इंजीनियरों को भेजेगा। वार्षिक लेखा विवरण का प्रलय ऐसा होगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए। प्राधिकरण द्वारा रखा गया लेखा, चारों राज्यों के प्राधिकरण प्रतिनिधिया प्रतिनिधियों के निर्देशन के लिए खुला रहेगा।

(5) प्राधिकरण की निधि से संवितरण ऐसी रौप्य से किए जाएंगे जैसी प्राधिकरण विहित करे, प्राधिकरण अपने हृत्यों के निर्वहन में किसी आपात में ऐसा खर्च कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) प्राधिकरण द्वारा रखे गए लेखाओं की लेखा परीक्षा, भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या उसका नामनिर्देशिती करेगा जो प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं का ऐसे संत्रेक्षणों के भ्रष्टीत रहते हुए ऐसे वह करना चाहे, प्रमाणित करेगा, प्राधिकरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

की रिपोर्ट की प्रतियाँ, महालेखाकार और चारों राज्यों के सम्बद्ध मुक्य इंजीनियरों को भेजेगा तथा उसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा।

उपलब्ध 13: प्राधिकरण का विनिष्टक्षय

उपलब्ध 8 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों की आवश्यक प्राधिकरण के विनिष्टक्षय प्रतियाँ और चारों राज्यों पर आवश्यक कर होंगे। किन्तु, एक पुनर्विलोकन समिति होनी जो स्वप्रेरणा से या किसी पश्चकार-राज्य के आवेदन पर, प्राधिकरण के किसी विनिष्टक्षय का पुनर्विलोकन करेगी, अस्यावश्यक मामलों में, पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष, पश्चकार राज्य के आवेदन पर, पुनर्विलोकन में अंतिम विनिष्टक्षय होने तक प्राधिकरण के किसी आदेश के निष्पादन को रोक सकता है।

उपलब्ध 14: पुनर्विलोकन समिति

14(1) पुनर्विलोकन समिति में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे :—

- (i) केन्द्रीय सिवाई मंत्री—अध्यक्ष
- (ii) मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश—सदस्य
- (iii) मुख्य मंत्री, गुजरात—सदस्य
- (iv) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र—सदस्य
- (v) मुख्य मंत्री, राजस्थान—सदस्य

केन्द्रीय कृषि और तिवाई मंत्रालय, विवाई विभाग का संविध, पुनर्विलोकन समिति का मंत्रीत्रक होगा किन्तु उते मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाने की दशा में, उस राज्य का राज्यालय या उसका प्राविकृत प्रांतनिधि, पुनर्विलोकन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

14(2) चारों राज्यों के मुख्य मंत्री, अपने-अपने सिवाई मंत्रियों को वैकल्पिक सदस्य के रूप में या तो साधारणतया या विशेष रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकेंगे ऐसे मंत्रियों को मताधिकार, विनिष्टक्षय आदि करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।

14(3) पुनर्विलोकन समिति, प्राधिकरण के विनिष्टक्षय का ऐसे किसी अधिकैशन में पुनर्विलोकन कर सकेंगी जिसमें अध्यक्ष तथा पुनर्विलोकन समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। यह आगा की जाती है कि पुनर्विलोकन समिति के सभी विनिष्टक्षय सर्वसम्मत से होंगे। सर्वसम्मति से न हो पाने की दशा में वे सदस्यों के जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, अहमत से किए जाएंगे।

14(4) संयोजक पुनर्विलोकन समिति के प्रस्तावित अधिकैशन की अग्रिम सूचना, उसकी कार्यसूची और कार्यसूची टिप्पण, पश्चकार राज्यों को भेजेगा।

14(5) पुनर्विलोक्त समिति का विनियोग, सेक्रेटरी किया जाएगा और वह अनितम तथा मध्ये मध्ये पर आवश्यक होगा।

उपचारण 15: प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर सन्ति०र्माण

खण्ड X[V के उपचारण 16 में चिह्नित सीमा को छोड़कर और उनके सिवाय, परियोजनाओं का आयोगन और सन्ति०र्माण प्रत्येक राज्य, अपने अधिकरणों के माध्यम से कराएगा।

उपचारण 16 : सरदार सरोवर परियोजना यर प्राधिकरण के पर्यवेक्षी कार्य

(1) एक 1—सरदार सरोवर परियोजना के बायर और अनुबन्ध संकर्म की बाबत चारों पक्षकार राज्य वित्तीय रूप में प्रतिवेद्ध हैं उनमें से तीन, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एकल III—परियोजन के शक्ति प्रेसेन्ट की बाबत ऐसे ही प्रतिवेद्ध हैं। परियोजना के इन एकलों के तत्परतापूर्वक, मित्यायथितापूर्ण भीर भीषणनियादन के लिए भीर पक्षकार राज्यों की वित्तीय प्रतिवेदना को ध्यान में रखते हुए, यह बांधीय और आवश्यक है कि इन प्रयोगन के लिए एक सन्ति०र्माण सलाहकार समिति गठित की जाए।

अतः हम यह आवेद करते हैं कि सरदार सरोवर सन्ति०र्माण सलाहकार समिति नामक एक सलाहकार समिति का गठन, राजपत्र में अधिकरण के विनियोग के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर, किया जाए।

(2) सन्ति०र्माण सलाहकार समिति का एक पूर्णकालिक सचिव होगा जो मुख्य इंजीनियर भी पंचित का होगा तथा नियुक्ति भारत संघ द्वारा को जाएगा। समिति में व्यावस्थक अन्य कार्यकार्यालय होंगे।

(3) समिति में निम्नलिखित भी होंगे :—

(i) भारत सरकार में सिवाई का भारताधक सचिव—अध्यक्ष।

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जन आयोग (के० ज० प्रा०) या यदि अध्यक्ष प्रधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए के० वि० प्रा० का कोई सदस्य।

(iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विष्णुत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) या यदि अध्यक्ष प्रधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए के० वि० प्रा० का कोई सदस्य।

(iv) अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (न० नि० प्रा०) या यदि अध्यक्ष प्रधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए न०नि०प्रा० का कोई सदस्य।

(v) संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) कृषि भीर नियाई मंत्रालय, भारत सरकार (सिवाई विभाग)।

(vi) मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के वित्त विभाग के भारताधक सचिव।

(vii) गुजरात और राजस्थान राज्यों के कृषि विभाग के भारताधक सचिव।

(viii) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के वित्त विभाग के भारताधक सचिव।

(ix) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के ग्रामस्व विभागों या भूमि प्रबंधन सम्बन्धित अन्य विभाग के भारताधक गविव।

(x) गुजरात राज्य में परियोजना का सारांशक महाप्रबन्धक या मुख्य इंजीनियर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के परियोजना से सम्बद्ध मुख्य इंजीनियर।

(xi) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य बिजरी बोर्ड के अध्यक्ष।

(xii) पितोंव नगरपाल, गर्दार भरोवर परियोजना किसी विशिष्ट अधिकारित के लिए अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य की सहायी विभाग कर मर्केगा।

(4) सरदार सरोवर सन्ति०र्माण सलाहकार समिति :—

(i) इन संहीनों के लिए लैगार किए गए परियोजना प्राकृतिकों की संवेदी करेंगी, आवश्यक उपात्तरण करने का सुझाव देंगी और गवाह उपकारों के प्राकृतिक अनुसंधान के लिए प्राकृतिकों की निकारिण करेंगी ;

(ii) उन्हींही विशेषज्ञों और डिजाइनों के सबव में सभी प्रस्तावों की, जो उन लियो परियोजना राज्य द्वारा लिद्द किए जाएं, परीक्षा करेंगी और विकारिण करेंगी और जहाँ भी आवश्यक हो इन प्रयोगन के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करेंगी ;

(iii) जारीव नियंत्रित, परियोजना को अवैष्यवस्था और शोध परिणाम प्राप्त करने को बांधीयता को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के विभिन्न भागों के सन्ति०र्माण के कार्यक्रम की समर्पित रीति से जांच करेंगी और उस बाबत सिफारिण करेंगी ;

(iv) अनुसंधान कार्यक्रम के अनुसार संकर्म के सन्ति०र्माण और अन्य प्रयोगनों के लिए नियंत्रित की अपेक्षायों की जांच करेंगी और आवश्यक सिफारिण करेंगी ;

(v) समय-समय पर ऐसी लक्षीकों और वित्तीय विभागों के, जिन्हें यह परियोजना के सदम विष्यादन के लिए आवश्यक समझे, जांच करेंगी और परियोजना के विष्यादन के लिए नियोजित महाप्रबन्धक/मुख्य इंजीनियरों, अधीक्षण इंजीनियरों, कार्यपालक इंजीनियरों और उप-खण्ड अधिकारियों की उन की आबत सिफारिण करेंगी ;

(vi) विभिन्न बायों के कार्यों के लिए विनियोजितों की जांच करेंगी और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उनकी बाबत सिफारिण करेंगी ;

(vii) ऐसे सभी उप-प्राक्कलनों और संविधानों की, जिनकी लागत की बाबत मंजूरी देना महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों की प्रक्रिया से परे है, जांच करेंगी और उनकी बाबत सिफारिश करेंगी;

(viii) महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों से संकरी और व्यक्त, दोनों के लिए, प्राप्त प्रभावित रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेंगी और कार्य को शीघ्र करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही की, जहां प्रावश्यक है, सिफारिश करेंगी।

(5) सन्निमाण सलाहकार समिति के मुध्यालय समिति नियन्त करेंगी।

(6) सन्निमाण सलाहकार समिति अपने कारबार को त्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के प्रत्यायोजन संबंधी नियम बनाएंगी।

(7) सन्निमाण सलाहकार समिति की सिफारिशों समिति द्वारा सम्बद्ध सरकारों को भेजी जाएंगी और उसकी प्रतियां पुनर्विलोकन समिति और नमंदा नियन्त्रण प्राधिकरण को जानकारी के लिए भेजी जाएंगी।

(8) सन्निमाण सलाहकार समिति की सिफारिशों सामान्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा मान ली जाएंगी। किन्तु असहमति की दशा में, मामला पुनर्विलोकन समिति को भेज दिया जाएगा और पुनर्विलोकन समिति का विनियंत्रण अंतिम और सभी सम्बद्ध राज्यों पर आवृद्धकर होगा।

सरदार सरोवर बांध और भनुवरन संकर्म (एनट ए), विजली घर और उत्पादन मशीनरी (एकक-III) और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रत्येक मामले में भगले उप केन्द्र तक विद्युत प्रदाय के लिए संचारण लाइनों के सन्निमाण संबंधी सभी मामलों में, नमंदा नियन्त्रण प्राधिकरण केवल ऐसे क्षेत्रों का पालन करेगा जो खण्ड IV के उपखण्ड 16 के अधीन गठित की गई निमाण सलाहकार समिति पर विनियंत्रण इप से न्यागत नहीं होते हैं।

(9) सन्निमाण सलाहकार समिति, मरदार सरोवर परियोजना के एकक I और III का सन्निमाण पूरा होने के तीन वर्ष के पश्चात् विष्टित कर दी जाएगी। एकक I और III का निर्माणोत्तर प्रबंध नमंदा नियन्त्रण प्राधिकरण के पर्यावेक्षण के अधीन गुजरात करेगा।

(10) निमाण सलाहकार समिति का खर्च मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा राज्य समान रूप से धूम्र करेंगे।

उपखण्ड 17 :

1977 के सौ०एम०पी० 234 और 1977 के सौ०एम०पी० 201 में, भारत संघ, प्रधिकरण के आदेश द्वारा स्थापित किये जाने वाले तंत्र में भाग भेजे के लिये, यदि इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाये और प्रधिकरण का विनियंत्रण कार्यान्वित करने की बाबत अथवा सर्वोत्तम प्रयत्न करने के लिये सहमत है।

उपखण्ड 18 :

भारत संघ, प्रधिकरण के आदेशानुसार स्थापित किय जाने वाले तंत्र में निर्देश किये जाने पर, भाग भेजे और प्रधिकरण के विनियंत्रण को

क्रियान्वित करने की बाबत सर्वोत्तम उपाय करने के लिये सहमत हो गया है। तदानुसार हम भारत संघ को निवेश देते हैं कि वह प्रधिकरण के निर्देशों को, विशेष रूप से खण्ड 1(2), 4, 12(6), 13, 14 के अधीन दिये गये निर्देशों को और साधारणतः सभी अन्य निर्देशों को जहां तक उनका संबंध भारत संघ से है, क्रियान्वित करने के लिये प्रधिकरण के आदेशानुसार गठित तंत्र में भाग ने।

खण्ड XV: कार्यवाहियों के खाते के संबंध में आवेदन :

(i) गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य प्रधिकरण के समक्ष पेश होने की बाबत अपना खर्च स्वयं बहन करेंगे। प्रधिकरण का व्यय उपर्युक्त आरों राज्य समान भाग में बहन और संबल करेंगे। इन निर्देशों का संबंध अन्तर्राज्यी जल-विद्याद प्रधिनियम, 1956 की घारा 5(1) के अधीन निर्देशों में है।

(ii) गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य, उक्त प्रधिनियम, की घारा 5(3) के अधीन किये गये निर्देशों में प्रधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये किये गये खर्च को स्वयं बहन करेंगे। उपर्युक्त निर्देशों की बाबत प्रधिकरण का खर्च गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान बराबर भागों में बहन करेंगे और देंगे।

खण्ड XVI: प्रतिम प्रावेश के कुछ खण्डों के प्रबर्तन की व्यवस्था :

(खण्ड V में उल्लिखित) खण्ड III और IV के आवाचा सरदार सरोवर बांध के पूर्ण जलाशय स्तर और प्रधिकरण जल स्तर के संबंध में खण्ड VII में, लागत और लाभ के आवंटन के संबंध में खण्ड VIII में, सरदार सरोवर परियोजना की प्रयोग्यता के लिये मध्य प्रदेश द्वारा छोड़ा जाने वाले जल के संबंध में खण्ड IX में, ऐसे छोड़े गये जल के सिये गुजरात द्वारा मध्यप्रदेश को किये गये जाने वाले भुगतान के संबंध में खण्ड X में, सरदार सरोवर परियोजना के खर्च का सिचाई और शक्ति के बीच आवंटन संबंधी खण्ड XII में, गुजरात और राजस्थान के बीच सरदार सरोवर परियोजना की लागत के सिचाई संघटकों के आवंटन संबंधी खण्ड XIII में और तंत्र संबंधी खण्ड XIV में हमारे प्रावेश, प्रधिकरण के विनियंत्रण के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी भी समय पुनर्विलोकन के अधीन होंगे।

7 दिसम्बर, 1979

₹०/- बी० रामास्वामी

मध्यप्रदेश

₹०/- ए० के० सिन्हा

सदस्य

₹०/- एम० ग्रार० ए० बंभारी

सदस्य

[स० फा० 3/3/79-डॉ०० ई०]

,स० सी० पटेस, सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1979

S.O. 792(E).—Whereas the Central Government had constituted by notification No. S.O. 4054, dated the 6th October, 1969, issued under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Narmada Water Disputes Tribunal to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river, Narmada and the river valley thereof;

And whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government, under sub-section (2) of section 5 of the said Act, a report setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it;

And whereas upon consideration of the said decision, the Central Government and the Governments of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan made references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act and the Tribunal has, on such references, forwarded to the Central Government under that sub-section a further report giving such explanations and guidance as it deemed fit;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the decision of the said Tribunal as modified by the Tribunal with reference to the explanations and guidance given in its further report.

DECISION OF THE NARMADA WATER DISPUTES TRIBUNAL AS MODIFIED BY THE EXPLANATIONS AND GUIDANCE GIVEN IN ITS FURTHER REPORT***Final Order And Decision of the Tribunal****Clause 1 : Date of Coming Into Operation Of the Order**

This Order shall come into operation on the date of publication of the Decision of this Tribunal in the Official Gazette under Section 6 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.

Clause II : Determination Of The Utilisable Quantum Of Narmada Waters At Sardar Sarovar Dam Site

The Tribunal hereby determines that the utilisable quantum of waters of the Narmada at Sardar Sarovar Dam Site on the basis of 75 per cent dependability should be assessed at 28 Million Acre Feet (34,537.44 M. cu. m.).

Clause III : Apportionment of The Utilisable Quantum Of Narmada Waters

(1) The Tribunal hereby orders that out of the utilisable quantum of Narmada waters, (a) Madhya Pradesh is entitled to a share of 18.25 Million Acre Feet (22,511.01 M. cu. m.), (b) Gujarat is entitled to a share of 9 Million Acre Feet (11,101.32 M. cu. m.), (c) Rajasthan is entitled to a share of 0.5 Million Acre Feet (616.74 M. cu. m.) and (d) Maharashtra is entitled to a share of 0.25 Million Acre Feet (308.37 M. cu. m.);

(2) Further, it is clarified that the apportionment relates to actual withdrawals and not consumptive use;

(3) Within its share of water, each party State is free to make such changes in the pattern of water use and in the areas to be benefited within or outside the Narmada basin in its territory as it may consider necessary.

Clause IV : Order With Regard To Excess Waters And Sharing Of Distress

(1) The utilisable flow of Narmada in excess of the 28 Million Acre Feet (34,537.44 M. cu. m.) of utilisable flow in

any water year, i.e., from 1st of July to 30th of June of next calendar year is apportioned in the following ratios of allocation i.e., 73 for Madhya Pradesh, 36 for Gujarat, 1 for Maharashtra and 2 for Rajasthan;

(2) In the event of the available utilisable waters for allocation in any water year from 1st of July to 30th June of the next calendar year falling short of 28 Million Acre Feet (34,537.44 M.cu.m.) the shortage should be shared between the various States in the ratio of 73 for Madhya Pradesh, 36 for Gujarat, 1 for Maharashtra and 2 for Rajasthan;

(3) The available utilisable waters in a water year will include the waters carried over from the previous water year as assessed on the 1st of July on the basis of stored waters available on that date;

(4) The available utilisable waters on any date will be inclusive of return flows and exclusive of losses due to evaporation of the various reservoirs;

(5) It may be mentioned that in many years there will be surplus water in the filling period after meeting the storage requirements and withdrawals during the period. This will flow down to sea. Only a portion of it will be utilisable for generating power at Sardar Sarovar river-bed power-house, and the rest will go waste. It is desirable that water, which would go waste without even generating power at the last river-bed power-house, should be allowed to be utilised by the party States to the extent they can.

Gujarat is, therefore, directed that whenever water starts going waste to sea without generating power, or based on the information received from upstream gauging stations, it anticipates that water would so go waste, it shall inform the Narmada Control Authority (hereinafter referred to as the Authority) and designated representatives of all the concerned States. Gujarat shall also inform them when such flows cease. During the period of such flows, the party States, whose reservoirs are spilling and the spill water cannot be stored elsewhere, may utilise such flows from the said reservoirs as they like and such utilisation by the party States will not count towards allotment of supplies to them, but use of such water will not establish any prescriptive rights.

Clause V : Period of Operation of The Order of Apportionment

Our Orders with regard to the equitable allocation in Clauses III and IV are made subject to review at any time after a period of 45 years from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

Clause VI : Full Supply Level of The Navagam Canal

The Tribunal hereby determines that the Full Supply Level of Navagam Canal offtaking from Sardar Sarovar should be fixed at 91.44 m., (+300') at its head regulator with a bed gradient of 1 in 12,000 from head to 290 km. (mile 180), that is, upto the offtake of Saurashtra branch. From that point to Rajasthan border the bed gradient should be 1 in 10,000. These bed gradients may be changed by Gujarat and Rajasthan by mutual agreement. Gujarat and Rajasthan shall be at liberty to decide the canal capacity required by each in the light of water which would be expected to be available within their share.

Clause VII : Full Reservoir Level And Maximum Water Level Of The Sardar Sarovar Dam

The Tribunal hereby determines that the height of the Sardar Sarovar Dam should be fixed for Full Reservoir Level +138.68 m., (+455') and Maximum Water Level at +140.21 m., (+460'). Gujarat shall take up and complete the construction of the dam accordingly.

Clause VIII : Sharing Of Costs and Benefits

(1) (i) The Tribunal hereby determines that out of the net power produced at Navagam at canal head and river

bed power houses on any day the share of Madhya Pradesh will be 57 per cent; Maharashtra's share will be 27 per cent and Gujarat's share will be 16 per cent.

(ii) The party States shall make available in annual instalments their share of funds required according to approved construction programme and take all the necessary steps to complete the Sardar Sarovar Dam within ten years of the date of publication of the Final Order and Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

(2) The Tribunal makes the following further Orders:—

- (i) The power generated in the River Bed and Canal Power Houses at Navagam will be integrated in a common switchyard.
- (ii) Madhya Pradesh and Maharashtra will be entitled to get 57 per cent and 27 per cent respectively of the power available at bus bar in the switchyard after allowing for station auxiliaries.
- (iii) The above entitlement applies both to availability of machine capacity for peak loads and to the total energy produced in any day.
- (iv) The entitlement of power and energy for any day can be utilised fully or partly by the concerned States or sold to another participating State under mutual agreement. It cannot, however, be carried forward except under a separate agreement or working arrangement entered into among the affected parties.
- (v) Gujarat will construct and maintain the transmission lines needed to supply the allotted quantum of power to Madhya Pradesh and Maharashtra upto Gujarat State border, along an alignment as agreed to between the parties and if there is no agreement, along such alignment as may be decided by the Narmada Control Authority. The transmission lines beyond Gujarat State border shall be constructed and maintained by Madhya Pradesh and Maharashtra in their respective States.
- (vi) The power houses and appurtenant works including the machinery and all installations as well as the transmission lines in Gujarat State will be constructed, maintained and operated by Gujarat State or an authority nominated by the State.
- (vii) The authority in control of the Power Houses shall follow the directions of the Narmada Control Authority in so far as use of water is concerned.
- (viii) The scheme of operation of the Power Houses including the power required and the load to be catered for the different party States during different parts of the day shall be settled between the States at least one week before the commencement of every month and shall not be altered during the month except under agreement among the States or under emergencies.

If and when Sardar Sarovar Power Complex gets linked with the Regional or National Power Grid, the operation of the Sardar Sarovar Power Complex will be governed by such altered system conditions. But in that event the Narmada Control Authority should arrange to take such steps as are necessary to enable the three States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to get their entitlement of power and energy from the Sardar Sarovar Power Complex according to these orders.

(ix) The capital cost of the power portion of Navagam Complex shall comprise the following:—

- (a) Full cost of Unit III electrical works and control works pertaining thereto, upto and including the switchyard.
- (b) Full cost of transmission lines in Gujarat State constructed for supplying power to Madhya Pradesh and Maharashtra.

(c) 56.1 per cent of the net cost of common facilities such as Dam and Appurtenant Works i.e. Unit I of Sardar Sarovar Project, after allowing for credits, if any;

(d) 56.1 per cent of the credit given to Madhya Pradesh for the downstream benefits derived from Narmadasagar Dam.

(x) Madhya Pradesh and Maharashtra shall respectively pay to Gujarat 57 per cent and 27 per cent of the capital cost of the power portion of the Sardar Sarovar headworks worked out vide (ix) above. This amount shall be paid in annual instalments until the capital works are completed. Each instalment will be worked out on the basis of the budgeted figures of the concerned works at the commencement of each financial year and shall be set off and adjusted against actual figures at the end of the financial year.

(xi) In addition to the payments vide (x) above, Madhya Pradesh and Maharashtra shall also pay to Gujarat 57 per cent and 27 per cent respectively of the operation and maintenance costs of the Sardar Sarovar Power Complex each year. These payments are also to be based on budgeted figures at the commencement of each financial year and adjusted against actual cost at the end of the year.

(xii) Notwithstanding the directions contained hereinabove, the party States may, by mutual agreement, alter, amend, or modify any of the directions in respect of sharing of power and payment for it.

Clause IX : Regulated Releases to be made by Madhya Pradesh for the requirement of Sardar Sarovar Project

With regard to the quantum and pattern of regulated releases, the Tribunal makes the following Order:—

It has been agreed by the party States and decided by the Tribunal in its Order dated 8th October, 1974, that the utilisable quantity of water of 75 per cent dependability in the Narmada at Sardar Sarovar dam site should be assessed at 28 MAF (34, 537.44 M.cu.m.). The actual inflow of 75 per cent dependability, however, is only 33, 316.29 M.cu.m. (27.01 MAF) and this is brought up to utilisable quantity of 28 MAF (34, 537.44 M.cu.m.) by means of carryover in various reservoirs allowing for evaporation losses and regeneration. Out of 28 MAF (34, 537.44 M.cu.m.), 11, 101.32 M.cu.m. (9 MAF) has to be provided for Gujarat and 0.5 MAF (616.74 M.cu.m.) for Rajasthan at Sardar Sarovar. The requirements at Sardar Sarovar have to be met by releases by Madhya Pradesh and by inflows from the intermediate catchment, surplus to the requirements of Madhya Pradesh below Narmadasagar and Maharashtra. The releases from Maheshwar work out to 10,015.86 M.cu.m. (8.12 MAF). Making uniform monthly releases the amount of water to be released by Madhya Pradesh per month would be 834.65 M.cu.m. (0.677 MAF). The actual inflow in the river system, however, would vary from year to year and, therefore, the releases by Madhya Pradesh would also vary.

The inflow during the filling period, July to October, cannot be predicted at the beginning of the season. It is only in October that it would be fully known whether the particular year is a normal year or the extent to which it is a surplus or deficit year. Normally the releases by Madhya Pradesh during the filling period, therefore, would have to be more or less on the basis of the year yielding 28 MAF (34,537.44 M.cu.m.) utilisable quantity. The month of July and early part of August are crucial for Kharif sowing. It is important that during this period regulatory arrangements should ensure that due share of water is made available to all parties.

Having regard to the facts mentioned in the preceding two paragraphs, we order that detailed rules of regulation and water accounting shall be framed by Narmada Control Authority in accordance with the guidelines given below. These guidelines may, however, be altered, amended or modified by agreement between the States concerned.

- (i) The 28 MAF (34,537.44 M.cu.m.) utilisable supplies of 75 per cent dependability in a water year (1st July to 30th June next year) shall be shared by the party States as under :—

Madhya Pradesh	— 18.25 MAF (22,511.01 M.cu.m.)
Gujarat	— 9.00 MAF (11,101.32 M.cu.m.)
Rajasthan	— 0.50 MAF (616.74 M.cu.m.)
Maharashtra	— 0.25 MAF (303.37 M.cu.m.)
	28.00 MAF (34,537.44 M.cu.m.)

- (ii) Surplus or deficit utilisable supplies in a water year shall be shared to the extent feasible by the party States in the same proportion as their allotted shares in (i) above. The surplus water shall first be utilised for filling up the reservoirs to capacity and surplus water shall be utilised for irrigation and other purposes only after that has been ensured.
- (iii) The water available in the live storages of the various reservoirs on 30th June shall be reckoned as an inflow to be shared in the next water year.
- (iv) The releases necessary to ensure Gujarat and Rajasthan's share of water in a water year shall be let down by Madhya Pradesh at a reasonably uniform rate, permitting only such variation as the Authority may direct or approve and keeping in view the directions for regulated releases.
- (v) The Authority shall ensure by so directing the releases by Madhya Pradesh that there is at all times sufficient utilisable water in Sardar Sarovar to meet the requirements of the next ten days, subject to water being available in the storages in Madhya Pradesh after taking into account the proportionate requirements of Madhya Pradesh. For this purpose, Gujarat and Rajasthan would intimate their requirements of the 10 daily period well in advance.
- (vi) Utilisation in a water year by each party State shall be figured out on the basis of actual daily discharge at canal head on every major and medium project. For minor works, it shall be on the basis of area irrigated under different crops, the delta for each crop being approved by the Authority. For pumping schemes, drawing directly from the river, its tributaries or reservoirs, whether for irrigation, domestic or industrial use, water drawn shall be reckoned on the basis of the rated capacity of pumps and the number of hours they run. For a cross check, the seasonwise and cropwise area irrigated by each pumping scheme shall also be recorded, and if the figures of water drawn as worked out by the two aforesaid methods differ, the decision of the Authority as regards water drawn shall be final.
- (vii) Withdrawals from Sardar Sarovar for Navagam Canal for Gujarat and Rajasthan shall be measured at the head of Navagam Canal. The supply to Rajasthan shall be measured at Gujarat-Rajasthan border. The loss in the canal in carrying the supply for Rajasthan shall be determined by the Authority after the canal has been constructed and shall reckon against the share of Rajasthan.

Water let down into the river from Sardar Sarovar through power house turbines shall be measured on the basis of power generated by it and that escaped through the spillway measurement at the spillway.

Gujarat may let down water from Sardar Sarovar for its downstream use by making specific indent for it and such release shall reckon against its share. Such releases for downstream use shall be made through the turbines and the power so generated shared between Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat in the prescribed ratio. Water let down into the river from Sardar Sarovar except at the

specific indent of Gujarat shall not reckon against the share of Gujarat.

The water drawn from Sardar Sarovar for use in Madhya Pradesh and Maharashtra, as the case may be, shall reckon against the share of water of that State.

- (viii) For major and medium projects, water account shall be kept by 10 daily period. The last 10 daily period of a month may have 11 days, 10 days or less, depending upon the number of days in the month. For minor schemes water accounts shall be kept by crop season, kharif (July to October) rabi (November to March) and hot weather (April to June). For pumping schemes and domestic and industrial uses it shall be monthly.
- (ix) The water use by minor and pumping schemes in any ten daily period may provisionally be taken to be the same as in the corresponding period in the previous year on the basis of average use during the crop period. For final water account, however, it will be determined as in (vii) above.
- (x) Each State shall furnish to the Authority and make available to any party State desiring the same, such data and information as the Authority may require and ask for.
- (xi) The Authority shall arrange the review of the ten day releases made by Madhya Pradesh at least once a month and oftener as considered necessary for directing any change in the releases. It may designate a person for doing so.
- (xii) The Authority shall direct final adjustment to be made in the following water year of the use in excess of the authorised use, if any, by any State or States during the preceding water year by curtailing the share(s) of the State or States concerned which have used water in excess and make over the same to the State or States which have received short supplies. Water supplied to Rajasthan on any day in excess of 10 per cent over and above its indent shall reckon against use by Gujarat.

- (xiii) The Authority shall furnish the annual water account for the water year to the Governments of the party States by the end of August of the next water year. Each State may make any observation on the account and/or point out corrections in it, if any, within one month of its receipt. After making the necessary modifications, the Authority shall furnish to each party State the final annual water account for the water year by 31st October. The Authority shall cause the annual water account to be published each year.

Clause X : Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh for such regulated releases.

(1) Madhya Pradesh shall take up and complete the construction of Narmadasagar dam with FRL 262.13 m (860 ft.) concurrently with or earlier than the construction of Sardar Sarovar dam.

(2) The Tribunal further orders that Gujarat should credit to Madhya Pradesh each year 17.63 per cent of the expenditure on account of Narmadasagar dam in the financial year commencing from the year of taking up of the construction of Narmadasagar dam. This will be initially credited on the basis of budget allotment to be adjusted at the end of the year on actual expenditure. The post construction expenditure on maintenance is not to be considered as cost of construction.

Clause XI : Directions Regarding Submergence, Land Acquisition and Rehabilitation of Displaced Persons.

Sub-clause 1 : Definitions.

1(1) : "Land".—The expression "land" shall have the same meaning as defined in the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter referred to as the Act) which states "the expression 'land' includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth."

1(2) : "Oustee".—An "ouste" shall mean any person who since at least one year prior to the date of publication of

the notification under Section 4 of the Act, has been ordinarily residing or cultivating land or carrying on any trade, occupation, or calling or working for gain in the area likely to be submerged permanently or temporarily.

1(3) : "Family".—(i) A family shall include husband, wife and minor children and other persons dependent on the head of the family, e.g., widowed mother.

(ii) Every major son will be treated as a separate family.

Sub-clause II.—Lands which are to be compulsorily acquired.

II(1) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall acquire for Sardar Sarovar Project under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, all lands of private ownership situated below the FRL + 138.68 m (455') of Sardar Sarovar and all interests therein not belonging to the respective States. If on the basis aforesaid, 75 per cent or more land of a contiguous holding of any person is required to be compulsorily acquired, such person shall have the option to compel compulsory acquisition of the entire contiguous holding.

II(2) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall also acquire for Sardar Sarovar Project under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, all buildings with their appurtenant land situated between FRL + 138.68 m (455') and MWL + 141.21 m (460') as also those affected by the backwater effect resulting from MWL + 141.21 m (460')

II (3) : The backwater level at the highest flood level in Sardar Sarovar shall be worked out by the Central Water Commission in consultation with Madhya Pradesh and Gujarat.

Sub-clause III.—Liability of Gujarat to pay compensation for Land Acquisition and Rehabilitation etc.

III(1) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs including compensation charges and expenses incurred by them for or in respect of the compulsory acquisition of lands required to be acquired as aforesaid.

III(2) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union of India compensation for the respective Government lands and structures on principles similar to those underlying the Land Acquisition Act, 1894. Where any dispute or difference arises between Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and the Union of India with respect to the compensation payable as aforesaid, any of the three States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra or the Union of India may refer the matter in dispute to arbitration. The State of Gujarat on the one hand and the States of Madhya Pradesh, Maharashtra or the Union of India (as the case may be) on the other hand shall respectively nominate one Arbitrator each. In the event of disagreement between the Arbitrators, such dispute or difference shall be referred to an Umpire who shall be a person appointed in that behalf by the Chief Justice of India from among persons who are, or have been Judges of the Supreme Court. The decision of the Arbitrators, or, as the case may be, of the Umpire shall be final and binding on the parties and shall be given effect to by them.

III(3) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra land revenue in accordance with the respective Land Revenue Codes of Madhya Pradesh and Maharashtra in respect of all lands in their respective territories acquired for Gujarat or conveyed to it.

III(4) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs, charges and expenses incurred by Madhya Pradesh and Maharashtra for the purpose of removal and reinstallation of any ancient or historical monuments, archaeological remains, religious place of worship or idols likely to be affected by submergence under Sardar Sarovar and that in the event of such payment being made, no separate compensation as hereinbefore provided shall be required to be paid in respect of the same having been affected by the submergence.

III(5) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs, charges and expenses required to be incurred by them for rehabilitation of oustees and oustees families in their respective territories in accordance with the directions hereinafter contained.

III(6) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra costs on account of establishment charges for land

acquisition and rehabilitation and other departmental staff which Madhya Pradesh and Maharashtra may consider necessary for the purpose of such acquisition and rehabilitation.

Sub-clause IV.—Provision for Rehabilitation.

IV(1) : According to the present estimates the number of oustees families would be 6147 spread over 158 villages in Madhya Pradesh, 456 families spread over 27 villages in Maharashtra. Gujarat shall establish rehabilitation villages in Gujarat in the irrigation command of the Sardar Sarovar Project on the norms hereinafter mentioned for rehabilitation of the families who are willing to migrate to Gujarat. For oustees families who are unwilling to migrate to Gujarat, Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra the cost, charges and expenses for establishment of such villages in their respective territories on the norms as hereinafter provided.

IV(2)(i) : According to the present estimates the number of oustees families below RL 106.68 metres (RL 350') would be 30 spread over 20 villages in Madhya Pradesh and 250 families spread over 20 villages in Maharashtra. Within six months of the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall determine by mutual consultation the location of one or two rehabilitation villages in Gujarat to rehabilitate oustees from areas below RL 106.68 metres (RL + 350'). Gujarat shall acquire necessary lands for the rehabilitation villages and make available the same within two years of the decision of the Tribunal. Within six months of the decision of the location of the rehabilitation villages in Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of oustees families from areas below RL 106.68 metres (RL 350') willing to migrate to Gujarat. For the remaining oustees families, Madhya Pradesh and Maharashtra shall arrange to acquire lands for rehabilitation within the respective States.

IV(2)(ii) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall set up adequate establishments for land acquisition and rehabilitation of oustees families. Gujarat shall deposit within three months of the decision of the Tribunal Rupees ten lakhs each with Madhya Pradesh and Maharashtra in advance towards cost of establishment and rehabilitation in these States to be adjusted after actual costs are determined. Madhya Pradesh and Maharashtra shall start land acquisition proceedings for areas below RL 106.68 metres (RL + 350'), within six months of the decision of the Tribunal and convey the lands to Gujarat for project purposes within three years of the decision of the Tribunal. Within 18 months of the decision of the Tribunal, Gujarat shall make an advance payment of Rs. 70 lakhs to Madhya Pradesh and Rs. 100 lakhs to Maharashtra towards the compensation of land, to be adjusted after actual costs are determined.

IV(2)(iii) : Regarding the oustees families from areas above RL 106.68 metres (RL + 350'), Gujarat shall intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra within six months of publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette the number and general location of rehabilitation villages proposed to be established by Gujarat in accordance with the decision of the Tribunal. Within one year of the receipt of proposal of Gujarat, both Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of oustees families willing to migrate to Gujarat. The three States by mutual consultation shall determine within two years of the decision of the Tribunal, the number and general location of rehabilitation villages required to be established by Gujarat in its own territory. Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of such villages to be established in Madhya Pradesh and Maharashtra and for which Gujarat would be required to make payments to Madhya Pradesh and Maharashtra respectively.

IV(2)(iv) : Gujarat shall acquire and make available a year in advance of the submergence before each successive stage, irrigable lands and house sites for rehabilitation of the oustees families from Madhya Pradesh and Maharashtra who are willing to migrate to Gujarat. Gujarat shall in the first instance offer to rehabilitate the oustees in its own territory.

IV(3) : Gujarat shall also provide the following grants and amenities to the oustees :—

(a) Resettlement Grants (Rehabilitation Grant)—Gujarat shall pay per family a sum of Rs. 750 inclusive of transportation charges as resettlement grant.

(b) Grant-in-aid.

In addition, Gujarat shall pay per family grant-in-aid in the following scale :—

Where total compensation is received	Grant-in-aid
Above Rs. 2000/-.	Nil.
Between Rs. 2000/- and Rs. 500/-.	Rs. 500/- less an amount equal to one-third of the compensation in excess of Rs. 500/-.
Less than Rs. 500/-.	Rs. 500/-.

(c) Civic amenities :

1. One primary school (3 rooms) for 100 families.
2. One Panchayat Ghar for every 500 families.
3. One Dispensary for every 500 families.
4. One seed store for every 500 families.
5. One children's park for every 500 families.
6. One village pond for every 500 families.
7. Drinking water well with trough for every 50 families.
8. Each colony should be linked to main road by roads of appropriate standard.
9. One platform for every 50 families.
10. Every oustee family shall be entitled to and allotted a house site i.e., a plot of land measuring $18.29 \times 27.43\text{m.}$ ($60' \times 90'$) free of cost. In addition, a provision of 30 per cent additional area for roads, Government buildings, open space etc. shall be made by Gujarat under civic amenities.

11. The State of Gujarat shall make the following provision for rehabilitation in Madhya Pradesh and Maharashtra :

	Rs.
(a) Resettlement	750 per family.
(b) Grant-in-aid	500 per family.
(c) Acquisition of land for resettlement of families affected @ 0.40 hectares (one acre) for 6 families	1500 per acre.

(d) Civic amenities:

1. One primary school @ 100 families 30000 each.
2. One Community Hall-cum-Panchayat Bhavan @ 500 families 20000 each.
3. One Dispensary @ 500 families 25000 each.
4. One seed store @ 500 families 10000 each.
5. One Children's Park @ 500 families 6000 each.

6. One Well with trough @ 50 families 10000 each.
7. One pond @ 500 families 20000 each.
8. One tree platform @ 50 families 1500 each.
9. One religious place of worship @ 100 families 1000 each.
10. Construction of approach roads and link roads for Abadies 3 km per every new Abadi 30000 per km.
11. Electrical distribution lines and street lights 2 km per 100 families 11000 per km.
12. Social amenities for each municipal town going under submergence, viz., water supply and sanitary arrangements layout, levelling of site etc. 5,00,000 each town

IV (4)(i) : Gujarat is directed to provide for rehabilitation and civic amenities as per directions contained hereinabove in Sub-clause IV(3) in its estimate for B-Land compensation and rehabilitation.

IV(4)(ii) : Notwithstanding the provisions hereinbefore contained, Gujarat shall not be liable to pay any compensation for the loss of public properties, facilities or amenities such as drinking water wells, primary school buildings, internal roads, village sites, approach roads, dispensaries, Panchayat buildings, rural electrification, highway bridges, telegraph lines, power lines, etc., if corresponding alternative properties, facilities or amenities are to be provided at the cost of the Sardar Sarovar Project. The party owning the facility shall have the option to accept compensation for utilities as existing or ask for their replacement or relocation at the cost of Gujarat.

IV(5) : It is made clear that the monetary values in Clause IV(3)(c) are liable to be changed at the time of actual rehabilitation. Where any dispute or difference arises as regards the changed valuation, the matter shall be determined by Arbitration in the manner provided in Clause III(2) above and Gujarat's liability shall stand altered accordingly.

IV(6)(i) : In the event of Gujarat being unable to resettle the oustees or the oustees being unwilling to occupy the area offered by Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall make such provisions for rehabilitation, civic amenities etc. on the lines mentioned in Clauses IV(1) to (4) above. Gujarat shall, in that event, be liable to pay all such expenses, costs etc., arising out of or in connection with rehabilitation and provision of civic amenities for the oustees including the cost of all acquisition proceedings and payment of compensation etc., as per the Land Acquisition Act, for the land allotted to oustees for cultivation and habitation.

IV(6)(ii) : In no event shall any areas in Madhya Pradesh and Maharashtra be submerged under the Sardar Sarovar unless all payment of compensation, expenses and costs as aforesaid is made for acquisition of land and properties and arrangements are made for the rehabilitation of the oustees the reform in accordance with these directions and intimated to the oustees.

IV(7) : Allotment of Agricultural Lands.—Every displaced family from whom more than 25 per cent of its land holding is acquired shall be entitled to and be allotted irrigable land to the extent of land acquired from it subject to the prescribed ceiling in the State concerned and a minimum of 2 hectares (5 acres) per family, the irrigation facilities being provided by the State in whose territory the allotted land is situated. This land shall be transferred to the ousted family if it agrees to take it. The price charged for it

would be as mutually agreed between Gujarat and the concerned State. Of the price to be paid for the land a sum equal to 50 per cent of the compensation payable to the oustee family for the land acquired from it will be set off as an initial instalment of payment. The balance cost of the allotted land shall be recovered from the allottee in 20 yearly instalments free of interest. Where land is allotted in Madhya Pradesh or Maharashtra, Gujarat having paid for it vide Clause IV(6)(i) supra, all recoveries for the allotted land shall be credited to Gujarat.

IV(8): Any dispute between the State in respect of Clauses IV(1) to (7) of these directions shall be referred to and determined by arbitration in the manner provided in Clause III(2) of these directions.

Sub-clause V. Programme for Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh and Maharashtra

V(1): As soon as practicable after the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette, Gujarat shall prepare and furnish to the other party States, a fresh estimate of sub-head B-Land for the Sardar Sarovar Project as permitted by the Tribunal including in particular, costs of acquisition of lands in Madhya Pradesh and Maharashtra and of rehabilitation of oustee families in Madhya Pradesh and Maharashtra.

V(x)(i): As soon as practicable after the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette and in any case before expiry of three months thereafter, both Madhya Pradesh and Maharashtra shall furnish to Gujarat three sets of Majmuli/Taluka maps of all talukas in their respective territories likely to be submerged wholly or partly under Sardar Sarovar. These maps shall indicate village boundaries. Within three months after the receipt of the Majmuli/Taluka maps Gujarat shall mark thereon the boundary of the area situated below the FRL as also that between FRL and MWL including the area affected by back water resulting from MWL and shall return one respective set so marked to Madhya Pradesh and Maharashtra.

V(2)(ii): As soon as practicable after the receipt of one set of the Majmuli/Taluka maps marked as aforesaid and in any case within six months thereof, the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra shall publish notifications under Sub-section (1) of Section 4 of the Act notifying that the lands in their respective territories situated below the FRL and buildings with their appurtenant lands between FRL and MWL, as also those affected by the back water effect resulting from MWL (to be specified in the notification) are likely to be needed for the Sardar Sarovar Project.

V(2)(iii): As soon as practicable after publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette as hereinbefore referred to and in any case within one year thereof, Gujarat shall intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra yearwise programme of construction of the dam.

V(2)(iv): Objections, if any, received against the proposed acquisition of lands as notified under Section 4 of the Act shall be heard and disposed of and any reports to the State Governments as contemplated by Sub-section (2) of Section 5A of the Act shall be made with utmost expedition. The Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra shall issue requisite notifications under Section 6 of the Act with utmost expedition and in any case before the expiry of three years from the dates of publication of the respective notifications under Sub-section (1) of Section 4 of the Act.

V(2)(v): As soon as practicable, after receipt of the yearwise programme of construction of the Sardar Sarovar Dam from Gujarat both Madhya Pradesh and Maharashtra in consultation with Gujarat shall finalise their respective yearwise programme of completing the proceedings for compulsory acquisition of lands in their respective territories upto the stages of making awards under Section 11 of the Act and of taking possession of the lands under Section 16 of the Act.

V(3)(i): Gujarat is required to pay to Madhya Pradesh and Maharashtra compensation for compulsory acquisition of lands, market value of Government lands to be conveyed to Gujarat and expenditure to be incurred in connection with

the rehabilitation of oustee families to be rehabilitated in Madhya Pradesh and Maharashtra as hereinbefore provided. Madhya Pradesh and Maharashtra shall on or before 30th September of each year intimate to Gujarat the amounts required to be paid by Gujarat to Madhya Pradesh and Maharashtra respectively having regard to (a) the extent of lands in Madhya Pradesh and Maharashtra in respect of which awards are likely to be made under Section 11 of the Act (b) the extent of Government lands likely to be conveyed by Madhya Pradesh and Maharashtra to Gujarat during the next financial year and (c) the expenditure likely to be incurred by Madhya Pradesh and Maharashtra in connection with rehabilitation of oustee families in Madhya Pradesh and Maharashtra during the next financial year. In arriving at these estimates for the next financial year, Madhya Pradesh and Maharashtra shall also take into account the differences, if any, between the payments made by Gujarat in pursuance of this clause for the current financial year and the amount actually payable during the said financial year.

V(3)(ii): On the basis of these estimates, Gujarat shall on or before the 31st May of the following financial year make payments to Madhya Pradesh and Maharashtra of the amounts estimated as provided in Clause V(3)(i) above.

V(3)(iii): Gujarat shall at each successive stage of submergence intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra the area coming under submergence at least 18 months in advance. The inhabitants of the area coming under the respective stages of submergence will be entitled to occupy or use their properties without being required to pay anything for such occupation and use till a date to be notified by the State concerned which date shall not be less than six months before submergence. They must vacate the area by the notified date.

V(4)(i): On payment of the amounts to be paid each year by Gujarat as compensation for compulsory acquisition of lands as aforesaid, Madhya Pradesh and Maharashtra shall, as expeditiously as possible, complete the acquisition and transfer such lands to Gujarat so as to vest the lands in Gujarat to be used only for the purpose of submergence and subject to Clauses V(5) to (8) of these directions.

V(4)(ii): On payment of the market value of Government lands by Gujarat as hereinbefore provided Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union of India shall convey such lands to Gujarat so as to vest in Gujarat to be used only for the purpose of submergence and subject to Clauses V(5) to (8) of these directions.

V(5): Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra in accordance with the respective Land Revenue Codes, the amount of land revenue payable every year for the lands in their respective territories acquired for Gujarat or conveyed to it, at the rates prevailing in Madhya Pradesh and Maharashtra respectively from time to time.

V(6): Madhya Pradesh and Maharashtra, as the case may be, shall remit each year to Gujarat any revenue which they may derive from the cultivation of lands which get periodically exposed in Sardar Sarovar, after deducting collection charges for the same.

V(7): Notwithstanding vesting in Gujarat of the lands coming under submergence, Madhya Pradesh and Maharashtra shall continue to enjoy all rights of sovereignty intact over the submerged area in the respective States.

V(8): Madhya Pradesh and Maharashtra respectively shall be exclusively entitled to all rights of fishing, boating and water transportation over the part of lake over the submerged land within Madhya Pradesh and Maharashtra respectively, provided, however, that such right is not exercised to the prejudice of any utilities of the Sardar Sarovar Project or cause hindrance in the legitimate performance of their duties by the project personnel.

V(9): All residual rights not specifically transferred to Gujarat in respect of the lands coming under submergence shall continue to vest in the Government in whose territory they are situated.

V(10) : In the event of the said lands not being used for the purpose of submergence for which it is acquired, the State of Gujarat shall retransfer such land to Madhya Pradesh or Maharashtra as the case may be, subject to the condition that Madhya Pradesh and Maharashtra refund to Gujarat the amount of compensation received from Gujarat in respect of such land.

V(11) : In the event of any land acquired for rehabilitation of oustee families is not used for the purpose, it shall be returned to the original owner on payment, where feasible or otherwise disposed of and due credit given to Gujarat.

V(12) : All costs incurred by Gujarat on acquisition of land and rehabilitation of oustees in respect of Sardar Sarovar shall be charged to Sardar Sarovar Project estimate, Unit I—Dam and Appurtenant Works.

Sub-clause VI :

Nothing contained in Clause XI shall prevent the alteration, amendment and modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between all the party States.

Clause XII : Allocation of Cost of Sardar Sarovar Project between Irrigation and Power.

We determine that the cost of Unit I—Dam and Appurtenant Works—should be apportioned between Irrigation and Power as follows :—

Irrigation	-- 43.9 per cent
Power	-- 56.1 per cent

Clause XIII : Allocation of Irrigation Component of Cost Sardar Sarovar Project and between Gujarat and Rajasthan.

(a)(i) The irrigation component of the cost of Unit I of Sardar Sarovar Project (Dam and Appurtenant Works) should be shared by Gujarat and Rajasthan in the ratio of 18 : 1.

(a)(ii) Madhya Pradesh and Maharashtra shall contribute a pro rata share to the irrigation component of the cost of Sardar Sarovar Dam as also towards its operation and annual maintenance, for water drawn from Sardar Sarovar for use in their territory. The pro rata share shall be in proportion of the quantity of water so drawn to 9.5 MAF. The amount so contributed shall be credited to Gujarat and Rajasthan in the ratio of 18 : 1.

(b) The cost of Navagam Canal with its design approved by Narmada Control Authority shall be shared by the two States as under :—

- (i) The cost differential in respect of land, earth work and lining for the gradients proposed by Gujarat and that now prescribed, to be borne by Rajasthan in full.
- (ii) The actual cost of the canal less (i) above to be shared on cusec mile basis.

The actual cost should be shared by Gujarat and Rajasthan on cusec-mile basis in the first instance and on completion of the work the share cost shall be adjusted as indicated above. Rajasthan shall credit its share cost each year initially on the basis of budget allotment. This should then be adjusted at the end of the year to actual expenditure. The post-construction expenditure on maintenance is not to be considered as cost of construction.

Should any difference arise between Rajasthan and Gujarat on figures of cost in respect of Navagam Main Canal for purposes of sharing the cost, the matter shall be referred to the Narmada Control Authority and on such a reference its decision shall be final and binding.

Clause XIV : Setting up of Machinery for Implementing The Decision of the Tribunal.

We make the following orders with regard to setting up of machinery for implementing the decision of the Tribunal :—

Sub-Clause 1 : Constitution of the Authority.

(1) An inter-State administrative authority to be called Narmada Control Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') shall be established for the purpose of securing compliance with and implementation of the decision and directions of the Narmada Water Disputes Tribunal (herein referred to as the 'Orders').

(2) The Authority shall consist of seven high-ranking Engineer Members, of whom one each shall be of the rank of Engineer-in-Chief, Chief Engineer, or Additional Chief Engineer of the Irrigation Department, Power Department or the State Electricity Board appointed by the Government of each of the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan and three other eminent Engineers of a rank not less than that of a Chief Engineer to be appointed by the Central Government in consultation with the party States. One of the three Independent Members shall be nominated by the Central Government, as the Chairman of the Authority with a deliberative vote at meetings where decisions are taken on any matter affecting the interest of more than one State and he will be in charge of the administrative work of the Authority. The Central or State Government, as the case may be, shall have the power to remove or suspend from the Authority any Member who, in its opinion, is not suitable to continue as Member.

(3) Each Independent Member shall be a full-time Member and be appointed for a term not exceeding five years. The Members appointed by the State Governments shall be part-time Members. The appointing authority for Independent Member or that for part-time Member, as the case may be, shall determine the terms and conditions of appointment in each case. As far as practicable, the first appointment of the seven members of the Authority shall be made within three months from the date of publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette.

1(4) : Vacancies of Members.

On any vacancy occurring in the offices of the three independent Members, the Central Government shall appoint a person to such vacant office, and on any vacancy occurring in the office of the four Members other than the independent Members, the State Government by whom the Member whose office falls vacant was appointed shall appoint a person to the vacant office.

In case of illness or absence for any cause whatever of a Member, the Central Government or State Government by whom he was appointed (as the case may be) may appoint a person as an acting Member during such illness or absence and such acting Member shall, while so acting, have all the powers and perform all the duties and be entitled to the indemnities of the Member (vide Sub-clause 5) in whose stead he so acts, save and except that the next senior independent Member appointed by the Central Government and not the acting Member shall act as Chairman at business meeting of the Authority or as the Chairman of the Authority in the event of illness or absence of the Chairman of the Authority.

Sub-clause 2 : Secretary of the Authority :

The Authority shall employ a Secretary, who shall be an Engineer. He shall not be a Member of the Authority.

Sub-clause 3 : Quorum and Voting :

Five Members shall be a quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for the transaction of the business of the Authority except such business as the Authority may from time to time prescribe as routine. The Authority shall not prescribe as routine any business in which the interests of any two of the States are likely to be in conflict. For the transaction of routine business three Members shall be a quorum and in the absence of the Chairman of the Authority, the Chairman elected at the meeting shall have a deliberative vote and in the event of an equality of votes a casting vote also.

Subject as aforesaid the Members shall have equal powers.

Sub-clause 4 : Disposal of Business by the Authority.

(1) Subject to the provisions of Sub-clause 4(2), below, the Authority may dispose of any matter before it either by

circulation or by holding a meeting. However, it will be open to any Member of the Authority to require that a matter shall not be disposed of by circulation but at a meeting.

4(2) : On the following matters the Authority shall record its decision by a Resolution at a meeting in which the Chairman and all the Members from the party States are present :

- (i) Framing of Rules of Business;
- (ii) Delegation of functions to a Member or Secretary or any official of the Authority;
- (iii) Categorising any part of the business of the Authority as of a formal or routine nature ;
- (iv) Any other matter which any of the four party States require that it shall be decided at a meeting where all the members from the party States are present.

However, if any particular item under this Sub-clause cannot be disposed of at two successive meetings owing to the absence of one or more Members from the party States, it shall be disposed of under Sub-clause 3 of Clause XIV.

4(3) : Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own Rules for the conduct of its business.

4(4) : The Authority shall cause proper minutes or records of all its proceedings to be kept as a permanent record.

Sub-clause 5 * Indemnity of Members :

No Member, officer or employee of the Authority shall be liable for loss, injury or damages resulting from (a) action taken by such Member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority of the Orders, even though such action is later determined to be unauthorised, or (b) the negligent or wrongful act of omission of any other person, employed by the Authority and serving under such Member, officer or employee unless such Member, officer or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work.

Sub-clause 6 : Officers and Servants of the Authority.

The Authority may from time to time appoint or employ such and so many officers and servants as it thinks fit and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of the Central Government officers and servants. All such officers and servants shall as such be subject to the sole control of the Authority. The scales of pay and other service conditions shall be as applicable to Central Government employees.

Persons employed in the services of the four States may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit. The Authority shall arrange with the State Governments to spare the services of the persons employed in the State Governments for whole-time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority. The Authority may also make direct recruitment of any personnel or obtain the same from the Centre or other source as considered appropriate.

Sub-clause 7 : Administrative & Field Organisation Costs.

(1) : All expenses of the Authority (including the salary and expenses of the independent Members) shall be borne by the State Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan in equal shares. The expenses pertaining to a Member representing a State shall be borne by the State concerned. The cost of maintaining, operating and controlling the gauging and other hydrological stations in each State and the telecommunication systems for communicating the data shall be borne by the State concerned.

(2) The costs of construction of the storage power installations, diversion works, headworks and canal networks

shall be borne wholly by the State Government in whose territory the work is located except for works whose cost has been ordered by the Tribunal to be shared between two or more party States. Where the capital cost is thus shared, the operation and maintenance cost shall also be shared in the same proportion.

Sub-clause 8 : Powers, Functions & Duties of the Authority.

8(1) : The role of the Authority will mainly comprise co-ordination and direction. Normally all bilateral matters should be dealt with mutually by the States concerned and referred to the Authority only if there is a dispute.

8(2) : The Authority shall be charged with the power and shall be under a duty to do any or all things necessary, sufficient and expedient for the implementation of the Orders with respect to :

- (i) the storage, apportionment, regulation and control of the Narmada waters ;
- (ii) sharing of power benefits from Sardar Sarovar project;
- (iii) regulated releases by Madhya Pradesh;
- (iv) acquisition by the concerned State for Sardar Sarovar project of lands and properties likely to be submerged under Sardar Sarovar ;
- (v) compensation and rehabilitation and settlement of oustees ; and
- (vi) sharing of costs.

8(3) : In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall perform inter alia the following functions :—

- (i) Madhya Pradesh or Gujarat, as the case may be, shall submit to the Authority the Sardar Sarovar Project Report, the Narmadasagar Project Report, the Omkareshwar Project Report and the Maheshwar Project Report. The Authority shall point out to the States concerned, the Central Water Commission, the Central Electricity Authority and Planning Commission any features of these projects which may conflict with the implementation of the Orders of the Tribunal. Any subsequent changes in the salient features or substantial increase in cost in respect of dams, power houses and canal headworks shall be reported to the Authority for taking appropriate action in the matter.
- (ii) The Authority shall decide the phasing and shall co-ordinate construction programmes of the Narmadasagar project and Sardar Sarovar Unit II—Canals with a view to obtaining expeditiously optimum benefits during and after the completion of the construction of the projects, having due regard to the availability of funds.
- (iii) The Authority shall obtain from the concerned States periodical progress reports both as to works and expenditure, and shall on receipt of such reports review the progress of construction of different units of the projects and whenever necessary advise the State concerned on the steps to be taken to expedite the work, except in respect of Unit I—Dam and Appurtenant Works and Unit III—Power Complex of Sardar Sarovar Project. The States shall submit, in respect of projects in Sub-clause 8(3)(i), completion reports to the Authority.
- (iv) The Authority shall issue appropriate directions whenever necessary for timely and full compliance by the concerned States with the Orders of the Tribunal in the matter of acquisition for and making available to Gujarat lands and properties likely to be submerged under the Sardar Sarovar Project and in the matter of compensation and rehabilitation of oustees thereunder.
- (v) The Authority shall cause to be established, maintained, and operated by the State Governments con-

- cerned or any one or more of them, such stream and other gauging stations, equipped with automatic recorders where necessary, discharge, silt and evaporation observation stations and measuring devices as may be necessary from time to time for securing the records required for carrying out the provisions of the Orders. If deemed necessary, the Authority may require the installation, maintenance and operation by the State concerned of measuring devices of approved type at the head of main canals as also at the offtake of the canal for Rajasthan for measuring amount of water diverted from Narmada river system.
- (vi) Concurrent records shall be kept of the flow of the Narmada at all stations considered necessary by the Authority and the records correlated.
- (vii) The Authority shall frame rules of regulation and water accounting as per guidelines given in Clause IX. It shall determine the share of water of each State for every ten-day period for purposes of regulation and water accounting.
- (viii) The Authority shall ensure implementation of the Orders of the Tribunal in respect of (a) quantum and pattern of regulated releases by Madhya Pradesh; (b) payment for such regulated releases/sharing of costs.
- (ix) The Authority shall collect from the State concerned data of the areas irrigated by Narmada waters in each season, of power generated at each hydro-electric power station at and downstream of Narmadasagar, of withdrawals for domestic, municipal and industrial or any other purposes and of waters going down the river from Sardar Sarovar Project.
- (x) The Authority shall determine the volume of water flowing in the river Narmada and its tributaries in a water year (1st July to 30th June next year).
- (xi) The Authority shall determine from time to time the volume of water stored by each State in reservoirs and other storages and may for that purpose adopt any device or method.
- (xii) The Authority shall determine at appropriate periodic intervals the use of Narmada waters made by the States, or such of them as necessary, at any place or in any area at any time and for that purpose it may take note of all diversions or obstructions, whether natural or artificial or partly natural and partly artificial, from the river Narmada and its Tributaries and measure such use by any method as it deems fit.
- (xiii) The Authority or any of its duly authorised representative shall have power to enter upon any land and property upon which any project or development of any project, or any work of gauging evaporation or other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, operated or maintained by any State for the use of Narmada water. Each State through its appropriate departments shall render all co-operation and assistance to the Authority and its authorised representatives in this behalf.
- (xiv) The Authority shall meet as often as necessary and decide on a proper management of waters including in particular the manner and details of withdrawals of waters from the storages on the Narmada river system in accordance with the Orders. In particular, the Authority shall meet at the end of filling season, and review the availability of waters in the storages on the Narmada river system and decide upon the pattern of their regulation for the next irrigation season, taking into account the carryover storage.
- (xv) The Authority shall give directions for a phased programme of construction for generation and transmission of power in fulfilment of the shares of power allocated to the three States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat from Sardar Sarovar and for payments therefor in accordance with the

Orders of the Tribunal. The Authority shall also ensure that generation and transmission of power from Sardar Sarovar complex are in accordance with the Orders.

- (xvi) The Authority shall issue appropriate directions for the establishment, maintenance and operation of an effective system of flood forecasting and flood control, including reporting of heavy precipitation, and telecommunication systems. The safety of a structure shall primarily be the responsibility of the Chief Engineer in charge of the structure and no decision or order shall be binding on him if in his opinion the safety of the structure will be endangered thereby. The Authority shall publish annually and make available to party States the data regarding operation of reservoirs during floods.

8(4) : In the light of its experience, the Authority may modify or add to the functions enumerated hereinabove in Sub-clauses 8(3)(i) to (xvi) by a resolution.

8(5) : All the concerned States shall submit to the Authority all the relevant information called for by the Authority in connection with the Narmada Valley Development expeditiously.

Sub-clause 9 : Annual Report of the Authority.

The Authority shall prepare and transmit to each of the four States as early as possible and in any case before the end of the current Water Year (1st July to 30th June) an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year and to make available to each State on its request any information within its possession any time and always provide access to its record to the States and their representatives.

Sub-clause 10 : Records of the Authority and their Location.

The Authority shall keep a record of all meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the four States or their representatives at such times and under such regulations as the Authority may determine.

The location of the Central, Regional and Sub-regional offices of the Narmada Control Authority shall be determined by the Authority.

The headquarters of the Authority shall be at New Delhi till such time as it decides on its permanent location.

Sub-clause 11 : Contracts and Agreements.

The Authority shall enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it.

Sub-clause 12 : Financial Provisions.

(1) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the four States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally. The Governments of the four States shall provide the necessary funds to the Authority to meet all capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority for the discharge of its functions.

(2) On the constitution of the Authority each of the Governments of the four States shall contribute Rs. 5,00,000 (Rupees five lakhs) to the fund of the Authority in the first instance.

(3) The Authority shall in the month of September of each year prepare detailed estimate of the amounts of money required during the twelve months from the first day of April of the ensuing year, showing the manner in which it is proposed to expend such money. The Authority shall on or before the fifteenth of October forward a copy of such detailed estimate to the concerned Chief Engineers of the four States and indicate the amount required to be contributed by each State for the ensuing financial year. Each of the State Governments

shall pay to the Authority its contribution as indicated by the Authority on or before the 30th day of April of the ensuing year.

(4) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the close of each financial year prepare an Annual Statement of Accounts and send copies thereof to the Accountants General as well as the concerned Chief Engineers of the four States. The form of the Annual Statement of Accounts shall be such as may be prescribed by rules. The Accounts maintained by the Authority shall be open for inspection at all reasonable times by the four States through their duly authorised representative or representatives.

(5) Disbursement shall be made from the fund of the Authority only in such manner as may be prescribed by the Authority. The Authority may incur such expenditure as it may think fit to meet any emergency in the discharge of its functions.

(6) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller & Auditor General of India, or his nominee, who shall certify subject to such observations as he may wish to make on the annual accounts of the Authority. The Authority shall forward to the Accountants General and the concerned Chief Engineers of the four States copies of the Report of the Comptroller & Auditor General of India and shall include the same in its Annual Report.

Sub-clause 13 : Decision of the Authority.

The decisions of the Authority on all matters covered under Sub-clause 8 shall be final and binding on the four party States. However, there shall be a Review Committee which may suo motu or on the application of any party State review any decision of the Authority. In urgent cases the Chairman of the Review Committee may, on the application of the party State, grant stay of any order of the Authority pending final decision on review.

Sub-clause 14 : Review Committee.

14(1) : The Review Committee shall consist of five members including a Chairman as under :—

(i) Union Minister for Irrigation as the :	Chairman
(ii) Chief Minister of Madhya Pradesh :	Member
(iii) Chief Minister of Gujarat :	Member
(iv) Chief Minister of Maharashtra :	Member
(v) Chief Minister of Rajasthan :	Member

The Secretary of the Union Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Irrigation, shall be the Convenor of the Review Committee but shall not have any voting right.

In case there is President's rule in any of the States, the Governor of that State or his authorised representative will act as Member of the Review Committee.

14(2) : The Chief Ministers of the four States may nominate the respective Irrigation Ministers either generally or specially as the alternate Member with full powers of voting, taking decisions etc.

14(3) : The Review Committee may review the decision of the Authority at a meeting at which the Chairman and all the Members of the Review Committee are present. It is expected that the decisions of the Review Committee will be by consensus. Failing consensus it shall be by majority of votes of Members including the Chairman.

14(4) : Advance notice of the proposed meeting of the Review Committee, its agenda and agenda notes will be forwarded by the Convenor to the party States.

14(5) : The decision of the Review Committee shall be recorded in writing and shall be final and binding on all the States.

Sub-clause 15 : Construction Outside Jurisdiction Of The Authority.

The planning and construction of the projects will be carried out by each State through its own agencies, save and except to the extent prescribed in Sub-clause 16 of Clause XIV.

Sub-clause 16 : Supervisory Function Of The Authority Over Construction of Sardar Sarovar Project.

(1) The four party States have financial commitment in respect of Unit I—Dan and Appurtenant Works of the Sardar Sarovar Project and three of them, namely, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have such commitment in respect of Unit III—Power Cataract of the Project. With a view to ensuring efficient, economical and early execution of these Units of the Project, and taking into account the financial commitments of the party States, it is desirable and necessary that a Construction Advisory Committee should be constituted for the purpose. We, therefore, order that such an Advisory Committee to be called Sardar Sarovar Construction Advisory Committee should be set up within three months from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

(2) The Construction Advisory Committee shall have a whole-time Secretary of the rank of Chief Engineer to be appointed by Union of India and such other staff as may be necessary.

(3) The Committee shall comprise.

- (i) The Secretary to the Government of India, in charge of Irrigation—Chairman.
- (ii) Chairman, Central Water Commission (CWC), or a Member of the CWC representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (iii) Chairman, Central Electricity Authority (CEA), or a Member of the CEA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (iv) Chairman, Narmada Control Authority (NCA) or an Independent Member of NCA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (v) Joint Secretary (Financial Adviser) in the Union Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Irrigation).
- (vi) Secretaries in charge of Finance Department of Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan.
- (vii) Secretaries in charge of Irrigation Department of Governments of Gujarat and Rajasthan.
- (viii) Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (ix) Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department concerned with land acquisition of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (x) General Manager or Chief Engineers of Gujarat in-charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the Project.
- (xi) Chairman, State Electricity Boards of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (xii) Financial Adviser, Sardar Sarovar Project.

The Chairman may co-opt any other Member for any particular meeting.

(4) The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall :—

- (i) scrutinise the project estimates prepared for these works, advise necessary modifications and recommend the estimates for the administrative approval of the concerned Governments ;
- (ii) examine and make recommendation on all proposals pertaining to technical features and designs as may be referred to it by any of the party States and where necessary consult experts for the purpose.

- (iii) examine and make recommendation on the programme of construction of different parts of the project in a co-ordinated manner, keeping in view the funds available, the economics of the project and the desirability of obtaining quick results;
- (iv) examine the requirement of funds for the construction of works and other purposes according to the approved programme and make necessary recommendations;
- (v) examine and recommend, from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the General Manager/Chief Engineers, Superintending Engineers, Executive Engineers and Sub-Divisional Officers engaged in the execution of the project;
- (vi) examine and, where necessary, recommend specifications for various classes of work;
- (vii) examine and make recommendation on all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the General Manager/Chief Engineers;
- (viii) review progress reports, both for works and expenditure from the General Manager/Chief Engineers and recommend, where necessary, steps to be taken to expedite the work.

(5) The headquarters of the Construction Advisory Committee will be fixed by the Committee.

(6) The Construction Advisory Committee will frame rules regarding procedure and delegation of power for the purpose of carrying out its business.

(7) The recommendations of the Construction Advisory Committee shall be conveyed to the Governments concerned by the Committee and copies sent to the Review Committee and Narmada Control Authority for information.

(8) The recommendations of the Construction Advisory Committee shall normally be accepted by the State Governments concerned. In the event of any disagreement, the matter shall be referred to the Review Committee and the decision of the Review Committee shall be final and binding on all the concerned States.

In all matters relating to the construction of the Sardar Sarovar Dam and appurtenant works (Unit I), Power House and generating machinery (Unit III) and Transmission lines to feed power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat upto the next sub-station in each case, the Narmada Control Authority will carry out only such functions as do not specifically devolve upon the Construction Advisory Committee set up under Sub-Clause 16, Clause XIV.

(9) The Construction Advisory Committee will be dissolved after three years of the completion of construction of Units I and III of the Sardar Sarovar Project. The post-construction management of Units I and III will be by Gujarat under the supervision of the Narmada Control Authority.

(10) The expenditure of the Construction Advisory Committee will be borne by the four States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally.

Sub-clause 17

Nothing contained in this Order shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between all the States concerned.

Sub-clause 18 :

The Union of India has consented to participate in the Machinery to be established by the Order of the Tribunal, if so directed and to do its best to implement the decision of the Tribunal.

Accordingly, we direct the Union of India to participate in the Machinery set up by the Order of the Tribunal to implement the directions of the Tribunal specifically under Clauses 1(2), 4, 12(6), 13, 14 and generally to implement all the other directions so far as the Union of India is concerned.

Clause XV : Order As To Costs Of Proceedings.

- (i) The States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan shall bear their own costs of appearing before the Tribunal. The expenses of the Tribunal shall be borne and paid by the aforesaid four State in equal shares. These directions relate to the references under Section 5(1) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.
- (ii) The States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan shall bear their own costs of appearing before the Tribunal in the references under Section 5(3) of the said Act. The expenses of the Tribunal in respect of the aforesaid reference shall be borne and paid by the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan in equal shares.

Clause XVI : Period Of Operation Of Certain Clauses Of The Final Order.

In addition to Clauses III and IV (mentioned in Clause V), our Orders in Clause VII with regard to Full Reservoir Level and Maximum Water Level of the Sardar Sarovar Dam, Clause VIII with regard to Sharing of Costs and Benefits, Clause IX with regard to Regulated Releases to be made by Madhya Pradesh for the Requirement of Sardar Sarovar Project, Clause X with regard to Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh for such Regulated Releases, Clause XII with regard to Allocation of Costs of Sardar Sarovar Project between Irrigation and Power, Clause XIII with regard to Allocation of Irrigation Component of Cost of Sardar Sarovar Project between Gujarat and Rajasthan and Clause XIV as regards Machinery are all made subject to review at any time after a period of 45 years from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

December 7, 1979.

Sd/-
V. RAMASWAMI, Chairman

Sd/-
A. K. SINHA, Member

Sd/-
M. R. A. ANSARI, Member"

[F. 3/3/79-WDI]
C. C. PATEL, Secy.

